रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED No D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1976/फाल्गुन 30, 1897

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1976/PHALGUNA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

(नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1976)

का०आ० 1078.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० आर० नामजोशी, अधिवक्ता, बम्बई को राज्य बनाम श्री बी० पी० गरीवाला, भूतपूर्व मुख्य शरीफ तथा श्री अजीज सुलतान हाजीभाई, भूतपूर्व अभिकर्ता, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बम्बई के संबंधित विशेष पुलिस स्थापना के मामला आर० सी० सं० 80/71-में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बम्बई के न्यायालय या मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य किसी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के मुकदमें का संचालन करने हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/75/75-एवीडी-II]

बी० सी० वरजानी, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 28th February, 1976

S.O. 1078.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. R. Namjoshi, Advocate, Bombay, as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of the accused persons in case R. C. No. 60/71 of the Special Police Establishment, Bombay, in State Vs. Shri B. P. Garwala, Ex-Head Shroff and Shri Aziz Sultan Hajeebhoy, Ex-Agent, Union Bank of India, Bombay, before the court of the Chief Metropolitan Magistrate, Bombay, or in the Court of any other Metropolitan Magistrate nominated by the Chief Metropolitan Magistrate.

[No. 225/75/75-AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1976

का० आ० 1079.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 41-मलिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उगा जेठा परमार, वंकरवास, खोरासर गिर, ताल्लुका मलिया, जिला जूनागढ़ (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उगा जेठा परमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०/वि०सं०/41/75(20)]

ELECTION COMMISSION

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1976

S.O. 1079.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Uga Jetha Parmar, Vankar Vas, Khorasa Gir, Taluka Malia, District Junagadh (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975, to the Gujarat Legislative Assembly from 41-Maliya Constitency, as failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Uga Jetha Parmar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ/LA/41/75(20)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1976

का० आ० 1080.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के के लिए 135-पेटलाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हिम्मतभाई गिर्धाभाई पटेल, मालव भागोल, पेटलाद, जिला कैरा (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हिम्मतभाई गिर्धाभाई पटेल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०/वि०स०/135/75(21)]

ORDER

New Delhi, the 18th February, 1976

S.O. 1080.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Himathbai Girdhabhai Patel, Malav Bhagol, Petlad, District Kaira (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 135-Petlad Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Himatbhai Girdhabhai Patel to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ/LA/135/75(21)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1976

का० आ० 1081.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन के लिए 105-कोयम्बटूर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एन० मनिकम, 11/30, आर० एच० एस० शास्त्री मार्ग, रामनगर, कोयम्बटूर (तमिलनाडु), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एन० मनिकम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० तमिलनाडु/वि०स०/105/74(उप)/(74)]

ORDER

New Delhi, the 25th February, 1976

S.O. 1081.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri N. Manickam, 11/30, R. H. S. Sastry Road, Ramnagar, Coimbatore (Tamil Nadu), a contesting candidate for the bye-election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in February, 1974 from 105-Coimbatore West constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri N. Manickam to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/105/74(Bye)(74)]

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1976

का० आ० 1082.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 173-जलालपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोतीराम जैरामभाई पटेल, कडियावाड, नवसारी, ताल्लुका नवसारी जिला वुलसर (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोतीराम जैराम भाई पटेल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधानपरिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गज०/वि०स०/173/75/(22)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1976

S.O. 1082.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Motiram Jerambhai Patel, At Kadiawad, Navsari, Taluka Navsari, District Bulsar (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 173-Jalalpore constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Motiram Jerambhai Patel, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/173/75/(22)]

V. NAGASUBRAMANAIN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1976

का० आ० 1083.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 82-राजनगर (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्रकाश पासवान, ग्राम पो० महेशवारा माया खजौली, जिला दरभंगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग द्वारा एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रकाश पासवान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/82/72(218)]

ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st March, 1976

S.O. 1083.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Prakash Paswan, Village & P.O. Maheshwara, via Khajauli, District Darbhanga (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 82-Rajnagar (SC) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Prakash Paswan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/82/72(218)]

A. N. SEN, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976

का० आ० 1084.—केन्द्रीय सरकार, अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 (1917 का 5) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर अपील अधिकरण (अभिलेख नाशकरण) नियम, 1946 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आयकर अपील अधिकरण (अभिलेख नाशकरण) संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर अपील अधिकरण (अभिलेख नाशकरण) नियम, 1946 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट आयकर अपील अधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों को, उसके सामने स्तंभ 2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में नष्ट किए जा सकते हैं, अर्थात् :—

सारणी

अभिलेख या रजिस्टर	अवधि
(1)	(2)
1. अपील अभिलेख :	
(क) जहां प्रतिनिर्देश आवेदन दाखिल किया गया हो और केस का कथन किया जा चुका हो।	यथास्थिति उस न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अपील में पारित अधिकरण के अन्तिम आदेश की तारीख से छह वर्ष।
(ख) जहां प्रतिनिर्देश आवेदन दाखिल किया जा चुका हो किन्तु केस का कथन न किया गया हो।	आवेदन को नामंजूर करने वाले अधिकरण अथवा न्यायालय के आदेश की तारीख से छह वर्ष।
(ग) जहां कोई प्रतिनिर्देश आवेदन दाखिल न किया गया हो।	अपील का निपटारा करने वाले अधि- करण के आदेश की तारीख से छह वर्ष।
(घ) अर्जस अपीलें . .	यथास्थिति, अधिकरण का उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से छह वर्ष।
II. प्रतिनिर्देश आवेदन अभिलेख :	
(क) जहां केस का कथन किया जा चुका हो।	सम्बद्ध अपील में अधिकरण के अन्तिम आदेश की तारीख से छह वर्ष।
(ख) जहां केस का कथन न किया गया हो।	आवेदन को नामंजूर करने वाले अधि- करण/उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से छह वर्ष।
III. निपटारे का रजिस्टर	रजिस्टर में अपील के निपटारे की सबसे पश्चात् की तारीख से तीन वर्ष।
IV. अन्य अभिलेख (अपीलों के रजिस्टर और प्रतिनिर्देश आवेदन के रजिस्टर को अपवर्जित करते हुए जो कि स्थायी रूप से रख जाएंगे।	अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन वर्ष।

[सं० ए० 60011(1)/73-प्रशा०III(एल०ए०)]

एस० डी० सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 9th February, 1976

S.O.1084.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Destruction of Records Act, 1917 (5 of 1917), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Appellate Tribunal (Destruction of Records) Rules, 1946, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Income-tax Appellate Tribunal (Destruction of Records) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication of the official Gazette.

2. For rule 2 of the Income-tax Appellate Tribunal (Destruction in Records) Rules, 1946, the following shall be substituted, namely:-

"2. The records and registers of the Income-tax Appellate Tribunal specified in column 1 of the following Table may be destroyed at the end of the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof; namely:—

TABLE

Records or registers	Period
(1)	(2)
I. APPEAL RECORDS:	
(A) Where reference application has been filed and case stated.	6 years from the date of the Tribunal's final order in the appeal passed conformably to the judgment of the High Court or the Supeme Court, as the case may be.
(B) Where reference application has been filed but case not stated.	6 years from the date of the Tribunal's order/High Court order rejecting the application.
(C) Where no reference application has been filed.	6 years from the date of the Tribunal's order disposing of the appeal.
(D) Acquisition appeals.	6 years from the date of the order of the Tribunal or High Court, as the case may be.

1	2
II. Reference Application Records:	
(A) Where case stated.	6 years from the date of the Tribunal's final order in the connected appeal.
(B) Where case not stated.	6 years from the date of the Tribunal's order/High Court's order rejecting the application.
III. Register of Disposals	3 years from the latest date of disposal of appeal in the register.
IV. Other Records (excluding Register of Appeals and Register of Reference Application which shall be retained permanently).	3 years from the date of the last entry.

[No. A. 60011(1)/73-Adm. III(LA)]

N. D. SINHA, Under Secy.

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1976

का० आ० 1085.--दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों को, जो सभी हनाफी मुसलमान हैं, 1 मार्च, 1976 से दरगाह समिति, अजमेर के (उसके तीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों में) सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :--

1. श्री अमिनुद्दीन अहमद खां, लोहारू, सिविल लाइन्स जयपुर।
2. मौलाना मोहम्मद मियां फारुकी, इलाहाबाद।
3. मौलाना सईद अब्दुल हई, बंगलौर।

[सं० 11(3)/75-वक्फ]

हसनुद्दीन अहमद, उप-सचिव

(Legislative Department)

New Delhi, the 27th February, 1976

S.O. 1085.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government hereby appoints, with effect from the 1st March, 1976 (in the vacancies arising on the expiration of the term of office of three members), the following persons, all of whom are Hanafi Muslims, as members of the Durgah Committee, Ajmer, namely :—

1. Shri Aminuddin Ahmed Khan of Loharu, Civil Lines, Jaipur.
2. Maulana Mohammad Mian Farooqi, Allahabad.
3. Maulana Syed Abdul Hai, Bangalore.

[No. 11(3)/75-Wakf.]

HASANUDDIN AHMED, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंककारी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1976

का० आ० 1086.--भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) अधिसूचना सं० 1148 फा० सं० 404/169/75 आई० टी० सी० सी) तारीख 10 नवम्बर, 1975 में "एस०डी० मोहन्ती" और "जे० के० सरकार" के नामों के स्थान पर "एस० सी० मोहन्ती" और "टी०के० सरकार" पढ़ें।

[सं० 1203 (फा०सं० 404/169/75-आई०टी० सी०सी०)]

वी० पी० मित्तल, उप सचिव

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1976

आय-कर

का० आ० 1087.--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

संस्था

किशोर भारती, बानखेड़ी, जिला होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) यह अधिसूचना 1-4-75 से 31-3-77 तक प्रभावी रहेगी।

[सं० 1224 (एफ० सं० 203/39/74-आ० टी० ए०-II)]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 12th February, 1976

INCOME TAX

S.O. 1087.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Kishore Bharati, Bankheri, District Hoshangabad (Madhya Pradesh)

This notification is effective from 1-4-75 to 31-3-77

[No. 1224/F. No. 203/39/74-ITA. II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1976

का० आ० 1088.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) योजना, 1976 कही जायेगी ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की प्रथम अनुसूची के—

(1) पैराग्राफ 2 में शब्दों अर्थात् "निर्धारित स्थान तथा समय पर उसके सामने दस दिन के भीतर पेश करें" के स्थान पर शब्द अर्थात् "प्रथम नोटिस मिलने की तारीख के बाद, निर्धारित स्थान तथा समय पर उसके सामने दस दिन के भीतर पेश करें" पढ़े जायें।

(2) पैराग्राफ 3 में शब्दों अर्थात् "निर्धारित स्थान तथा समय पर दस दिन के भीतर उन्हें पेश करें" के स्थान पर शब्द अर्थात् "दूसरे और अंतिम नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के भीतर उन्हें निर्धारित स्थान और समय पर पेश करें" पढ़े जायें।

[सं० एफ० 2/1/75-बी० ओ० (1)]

(Department of Banking)

New Delhi, the 18th February, 1976

S.O. 1088.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 namely :—

1. (1) This Scheme may be called Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, in the First Schedule,

(i) in paragraph 2, for the words "produce before him within ten days at the stipulated place and time", the words "produce before him at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the first notice" shall be substituted;

(ii) in paragraph 3, for the words "produce them within ten days at the stipulated place and time", the words "produce them at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the second and final notice" shall be substituted.

[No. F. 2/1/75-BO. I(i)]

का० आ० 1089—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 1974 में और संशोधन करने के एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशकों की की नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 1976 कहे जाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम 1974 की अनुसूची के—

(1) पैराग्राफ 2 में शब्दों अर्थात् "निर्धारित स्थान तथा समय पर उसके सामने 10 दिन के भीतर पेश करें" के स्थान पर शब्द अर्थात् "प्रथम नोटिस मिलने की तारीख के बाद, निर्धारित स्थान तथा समय पर उसके सामने दस दिन के भीतर पेश करें" पढ़े जाएं ।

(2) पैराग्राफ 3 में शब्दों अर्थात् "निर्धारित स्थान तथा समय पर दस दिन के भीतर उन्हें पेश करें" के स्थान पर शब्द "दूसरे और अन्तिम नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से दस दिन भीतर उन्हें निर्धारित स्थान और समय पर पेश करें" पढ़े जाएं।

[सं० एफ० 2/1/75-बी० ओ० I(2)]

S.O. 1089.—In exercise of the powers conferred by section 49 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following rules further to amend the State Bank of India (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the State Bank of India (Appointment of Employee Directors) (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the State Bank of India (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974, in the Schedule,

(i) in paragraph 2, for the words "produce before him within ten days at the stipulated place and time", the words "produce before him at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the first notice" shall be substituted;

(ii) in paragraph 3, for the words "produce them within ten days at the stipulated place and time", the words "produce them at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the second and final notice" shall be substituted.

[No. F. 2/1/75-BO. I(ii)]

का० आ० 1090.—भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 39) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अनुषंगी बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 1974 में और संशोधन करने के एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम अनुषंगी बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 1976 कहे जायेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. अनुषंगी बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम 1974 की अनुसूची के—

(1) पैराग्राफ 2 में शब्दों अर्थात् "निर्धारित स्थान तथा समय पर उसके सामने दस दिन के भीतर पेश करें" के स्थान पर शब्द अर्थात् "प्रथम नोटिस मिलने की तारीख के बाद, निर्धारित स्थान और समय पर उसके सामने दस दिन के भीतर पेश करें" पढ़े जाएं ।

(2) पैराग्राफ 3 में शब्दों अर्थात् "निर्धारित स्थान और समय पर उस दिन के भीतर उन्हें पेश करें" के स्थान पर शब्द अर्थात् "दूसरे और अंतिम नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर उन्हें निर्धारित स्थान तथा समय पर पेश करें" पढ़ा जाए ।

[सं० एफ० 2/1/75-बी० ओ० I(3)]

ल० द० कटारिया, निदेशक

S.O. 1090.—In exercise of the powers conferred by section 62 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, (38 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Subsidiary Banks (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Subsidiary Banks (Appointment of Employee Directors) (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Subsidiary Banks (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974, in the Schedule —

(i) in paragraph 2, for the words "produce before him within ten days at the stipulated place and time", the words "produce before him at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the first notice" shall be substituted;

(ii) in paragraph 3, for the words "produce them within ten days at the stipulated place and time", the words "produce them at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the second and final notice" shall be substituted.

[No. F. 2/1/75-BO. I(iii)]

L. D. KATARIA, Director

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1976

का० आ० 1091.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में फरवरी 1976 के दिनांक 20 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	29,77,74,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट जारी किये गये	6449,08,69,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,51,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
कुल नोट		6478,86,43,000	विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,48,000
			रुपए का सिक्का		14,15,55,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		6160,44,40,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		..
कुल देयताएं		6478,86,43,000	कुल आस्तियां		6487,86,43,000

दिनांक 25 फरवरी, 1976

के० आर० पुरी, गवर्नर

20 फरवरी 1976 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	29,77,74,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,36,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	7,35,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	180,36,15,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	326,58,90,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	902,11,26,000
जमाराशियां :—		निवेश**	470,93,34,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	64,67,75,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	9,24,51,000	(ii) राज्य सरकारों को@	107,52,60,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	536,03,43,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	645,88,48,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,28,35,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	398,79,12,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,59,71,000	(iii) दूसरों को	14,12,75,000
(iv) अन्य बैंक	61,60,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,21,43,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	15,21,08,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	86,20,00,000
(ग) अन्य	1503,18,86,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,11,46,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देय बिल	178,21,60,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	90,56,95,000
अन्य देयताएं	910,09,01,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	369,26,61,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	523,17,24,000
रुपये	4239,94,82,000	रुपये	4239,94,82,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं ।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 45,02,50,000/- रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।

के० आर० पुरी, गवर्नर

[सं० फ० 10(1)76-बी०ओ०-1]

प० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

दिनांक : 25 फरवरी, 1976

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 25th February, 1976

S.O. 1091.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 20th day of February 1976.

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	29,77,74,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	6449,08,69,000		(a) Held in India	182,52,51,000	
Total notes issued		6478,86,43,000	(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	121,73,97,000	
			TOTAL		304,26,48,000
			Rupee Coin		14,15,55,000
			Government of India Rupee Securities		6160,44,40,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		..
Total Liabilities		6478,86,43,000	Total Assets		64,78,86,43,000

Dated the 25th day of February 1976.

K.R.PURI, Governor

Statement of Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on 20th February, 1976

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	29,77,74,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	2,36,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	7,35,000
National Agricultural Credit (Stabilisation)Fund	140,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(a) Internal	180,36,15,000
Deposits :—		(b) External	..
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	326,58,90,000
(i) Central Government	64,67,75,000	Balances Held Abroad*	902,11,26,000
(ii) State Governments	9,24,51,000	Investments**	470,93,34,000
(b) Banks		Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	536,03,43,000	(i) Central Government	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	17,28,35,000	(ii) State Governments @	107,52,60,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,59,71,000	Loans and Advances to:—	
(iv) Other Banks	61,60,000	(i)Scheduled Commercial Banks†	645,88,48,000
(c) Others	1503,18,86,000	(ii) State Co-operative Banks ††	398,79,12,000
Bills Payable	178,21,60,000	(iii) Others	14,12,75,000
Other Liabilities	910.09,01,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments	69,21 43,000
		(ii) State Co-operative Banks	15,21,08,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	86,20,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,11 46,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	90,56,95,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	369,26,61,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	523,17,24,000
Rupees	4239,94,82,000	Rupees	4239,94,82,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments

†Includes Rs. 45,02,50,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

K. R. PURI, Governor

Dated the 25th day of February, 1976

[N. F. 10(1)/76-BO I]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

का० आ० 1092.—राष्ट्रपति जी ने एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं अर्थात्:—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (चौथा संशोधन) नियमावली, 1976 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (जिसका इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लेख किया गया है) के नियम 74 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"74 के प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी:—ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो किसी राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होने हुए अथवा इतर सेवा पर होने हुए सेवा से निवृत्त होता है, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार पेंशन तथा सेवा निवृत्ति उपदान की मंजूरी की कार्यवाही इस संवर्ग प्राधिकरण के लेखा-परीक्षा अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष, जैसे भी मामला हो, द्वारा की जाएगी, जिसने सरकारी कर्मचारी की राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति अथवा इतर सेवा की स्वीकृति दी थी ।"

3. उक्त नियमावली के नियम 80 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"80 क. जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति पर होते हुए अथवा इतर सेवा पर होते हुए, हो जाये तो परिवार पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की अदायगी:—ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसकी मृत्यु किसी राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति पर होते हुए अथवा इतर सेवा पर होते हुए हो जाए, तो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार परिवार पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की अदायगी का प्राधिकार देने की कार्यवाही उस संवर्ग प्राधिकरण के लेखा-अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाएगी जिसने सरकारी कर्मचारी की राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति अथवा इतर सेवा की स्वीकृति दी थी ।"

[सं० फ० 11(1)-ई०वी०(ए)/76]

एस० एस० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1092.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and, after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relating to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 74, the following rule shall be inserted, namely :—

"74A. Government servants on deputation.—In the case of a Government servant who retires from service, while on deputation to a State Government or while on foreign service, action to sanction pension and gratuity in accordance with the provisions of this Chapter shall be taken by the Audit Officer or the Head of Office, as the case may be, of the cadre authority which sanctioned the deputation of the Government servant to the State Government or to foreign service."

3. After rule 80 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"80A. Payment of family pension and death-cum-retirement gratuity when a Government servant dies while on deputation to a State Government or while on foreign service.—In the case of a Government servant who dies while on deputation to a State Government or while on foreign service, action to authorize the payment of family pension and death-cum-retirement gratuity in accordance with the provisions of this chapter shall be taken by the Audit Officer or the Head of Office, as the case may be, of the cadre authority which sanctioned the deputation of the Government servant to the State Government or to foreign service."

[No. F-11(1)-EV(A)/76]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 15th January, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 1093.—In Board's Order No. 1140 (F. No. 404/169/75-ITCC) dated the 10th November, 1975 for the name "S. D. Mohanty" read "S. C. Mohanty".

[No. 1204/F. No. 404/169/75-ITCC]

V. P. MITTAL, Secy.

(आयकर विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

का० आ० 1094.—केन्द्र सरकार के अभिमत है कि धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के अनुसार वित्तीय वर्ष 1973-74 में जिनके शुद्ध धन रु० 10 लाख से अधिक होने पर कर निर्धारित की गई है उनके नाम तथा अन्य विवरण (निम्नलिखित) प्रकाशित करना आवश्यक और लोकहितानुकूल भी है । (i) निर्धारण वर्ष (ii) निर्धारित धन (iii) निर्धारित धन (iv) कर देय और (v) कर प्रदत्त ।

1. मिस० ए० डी० थेकर, कवनाटुटकरा, कुमरकम (i) 1970-71, (ii) रु० 1133591 (iii) रु० 1195500 (iv) रु० 11887 (v) रु० 11387, (i) 1971-72 (ii) रु० 982454 (iii) रु० 1001800 (iv) रु० 14054, (v) रु० 14054, 2. श्रीमती ग्लाडीस एस० बोडर, कोच्चिन-1 (i) 1970-71 (ii) रु० 851177 (iii) 1046800 (iv) रु० 7205 (v) रु० 7205 (i) 1972-73 (ii) 1111767 (iii) रु० 1111500 (iv) रु० 14234

(V) 14234 (I) 1973-74 (II) रु० 158600 (III) रु० 11858 (VI) रु० 16260 (V) रु० 16260 (3) श्री जेम्स जेकब, कोच्चिन शिप्पिंग कंपनी, कोच्चिन (I) 1970-71 (II) रु० 917369 (III) रु० 1119700 (IV) रु० 9992 (V) रु० 8000 (4) जेम्स जेकब, कोच्चिन शिप्पिंग कंपनी, कोच्चिन (I) 1971-72 (II) रु० 1066657 (III) रु० 1261500 (VI) रु० 21845 (V) रु० 13558 (I) 1972-73 (II) रु० 1044815 (III) रु० 1190600 (IV) रु० 20718 (V) रु० 16344 (I) 1973-74 (II) रु० 1124700 (III) रु० 1129300 (VI) रु० 18879 (V) रु० 18742 (5) श्री एम० सी० मात्यू, कालिकट (I) 1973-74, (II) रु० 1112190 (III) रु० 1040800 (VI) रु० 16224 (V) रु० 16224 (6) श्री नीलिकन्डि कुंजहम्मद् हाजि, कलपेटा (I) 1972-73 (II) रु० 1016380 (III) रु० 1070200 (IV) रु० 17107 (V) रु० 12000 (7) श्री एम० सी० पोत्तन (सीनियर) कालिकट (I) 1970-71 (II) रु० 1226930 (III) 1094700 (IV) रु० 9368 (V) रु० 9368 (8) श्री एम० सी० पोत्तन (जुनियर) (I) 1969-70 (II) रु० 859830, (III) रु० 1137370 (IV) रु० 10410 (V) रु० 10410 (I) 1970-71 (II) रु० 1662300 (III) रु० 1955570 (IV) रु० 28480 (V) रु० 28180 (I) 1971-72 (II) रु० 1350440 (III) रु० 1790970 (IV) रु० 40672 (V) रु० 37205 (I) 1972-73 (II) रु० 1307610 (III) रु० 1705770 (IV) रु० 46576 (V) कुछ नहीं (9) राम वर्मा वलियकोयिल तंपुरान, सेटलमौन्ट पेलेस, पूजपुरा, तिरुवनन्तपुरम (I) 1971-72 (II) रु० 764890 (III) रु० 1287300 (IV) रु० 22619 (V) रु० 22619 (I) 1972-73 (II) रु० 1115940 (III) रु० 1325580 (IV) रु० 24767 (V) रु० 24767 (I) 1973-74 (II) रु० 1670700 (III) रु० 1824450 (4) रु० 55956 (V) रु० 55956 (10) जी० सुरेषचन्द्रन नायर, द्वारा/पी० गोपिनाथन नायर, नलन्दा, कोल्लम (I) 1974-75 (II) रु० 1209600 (III) रु० 1209600 (IV) रु० 21288 (V) रु० 21288 (11) जी० सतीषचन्द्रन नायर, द्वारा/पी० गोपिनाथन नायर, नलन्दा, कोल्लम (I) 1974-75 (II) रु० 1232300 (III) रु० 1232300 (IV) रु० 21969 (V) 21969 (12) श्री के० तोमस जेकब, कोच्चिन शिप्पिंग कंपनी कोच्चिन (I) 1970-71 (II) रु० 1379993 (III) रु० 1570000 (IV) रु० 21250 (V) रु० 21250 (13) तोमस जेकब, कोच्चिन शिप्पिंग कंपनी, कोच्चिन-1 (I) 1971-72 (II) रु० 1385908 (III) 1521000 (IV) रु० 29840 (V) रु० 25578 (I) 1972-73 (II) रु० 1402200 (III) रु० 1507770 (IV) रु० 30616 (V) रु० 27066 (I) 1973-74 (II) रु० 1391533 (III) रु० 1396300 (IV) रु० 26889 (V) रु० 26746 (14) वी० वेलायुधन तंभी, वडश्शेरी अम्मा वीडु, पेरुतान्नी, तिरुवनन्तपुरम (I) 1973-74 (II) रु० 1266000 (III) रु० 1213000 (IV) रु० 57187 (V) रु० 57187

[सी० सं० 188/बी०/टेक०75-76]

आर० श्रीकण्ठन नायर, आयकर अधिकारी (मुख्यालय-II)

कृते आयकर आयुक्त, केरल I & II

Income-tax Department

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1094.—The Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and other particulars relating to the following Individuals who have been assessed under the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) on the net wealth exceeding Rs. 10 lakhs during the financial year 1973-74 showing the details as (i) assessment year, (ii) wealth returned, (iii) wealth assessed, (iv) tax payable and (v) tax paid.

1. Miss. A. D. Baker, Kavanattukara, Kumarakom, (i) 1970-71, (ii) Rs. 1133591, (iii) Rs. 1195500, (iv) Rs. 11887, (v) Rs. 11387, (i) 1971-72 (ii) Rs. 982454, (iii) Rs. 1001800, (iv) Rs. 14054, (v) Rs. 14054, (2) Smt. Gladys S. Koder, Cochin-1, (i) 1970-71, (ii) Rs. 851177, (iii) Rs. 1046800, (iv) Rs. 7205, (v) Rs. 7205. (i) 1972-73, (ii) Rs. 1111767, (iii) Rs. 1111500, (iv) Rs. 14234, (v) Rs. 14234. (i) 1973-74, (ii) Rs. 1158600, (iii) Rs. 115800, (iv) Rs. 16260, (v) Rs. 16260. (3) Sri. James Jacob, Cochin Shipping Co., Cochin (i) 1970-71, (ii) Rs. 917369, (iii) Rs. 1119700, (iv) Rs. 9992, (v) Rs. 8000. (4) James Jacob, Cochin Shipping Co., Cochin (i) 1971-72, (ii) Rs. 1066657, (iii) Rs. 1261500, (iv) Rs. 21845, (v) Rs. 13558, (i) 1972-73, (ii) Rs. 1044815, (iii) Rs. 1190600, (iv) Rs. 20718, (v) Rs. 16344, (i) 1973-74, (ii) Rs. 1124700, (iii) Rs. 1129300, (iv) Rs. 18879, (v) Rs. 18742. (5) Sri. M. C. Mathew, Calicut, (i) 1973-74, (ii) Rs. 1112190, (iii) Rs. 1040800, (iv) Rs. 16224, (v) Rs. 16224. (6) Shri Neelikandy Kunhammed Haji, Kalpeta, (i) 1972-73, (ii) Rs. 1016380, (iii) Rs. 1070200, (iv) Rs. 17107, (v) Rs. 12000. (7) Sri M. C. Pothen (Sr.) Calicut (i) 1970-71, (ii) Rs. 1226930, (iii) Rs. 1094700, (iv) Rs. 9368, (v) Rs. 9368. (8) Sri M. C. Pothen (Jr.) (i) 1969-70, (ii) Rs. 859830, (iii) Rs. 1137370, (iv) Rs. 10410, (v) Rs. 10410, (i) 1970-71, (ii) Rs. 1662300, (iii) Rs. 1955570, (iv) Rs. 28480, (v) Rs. 28480, (i) 1971-72, (ii) Rs. 1350440, (iii) Rs. 1790970, (iv) Rs. 40672, (v) Rs. 37205, (i) 1972-73, (ii) Rs. 1307610, (iii) Rs. 1705770, (iv) Rs. 46576, (v) Nil. (9) Rama Varma Valiakoil Thampuran, Setalmond Palace, Poojapura, Trivandrum (i) 1971-72, (ii) Rs. 764890, (iii) Rs. 1287300, (iv) Rs. 22619, (v) Rs. 22619, (i) 1972-73, (ii) Rs. 1115940, (iii) Rs. 1325580, (iv) Rs. 24767, (v) Rs. 24767, (i) 1973-74, (ii) Rs. 1670700, (iii) Rs. 1824450, (iv) Rs. 55956, (v) Rs. 55956. (10) G. Sureshchandran Nair, C/o Gopinathan Nair, Nalanda, Quilon (i) 1974-75 (ii) Rs. 1209600, (iii) Rs. 1209600, (iv) Rs. 21288, (v) Rs. 21288. (11) G. Satheeshchandran Nair, C/o P. Gopinathan Nair, Nalanda, Quilon (i) 1974-75, (ii) Rs. 1232300, (iii) Rs. 1232300, (iv) Rs. 21969, (v) 21969. (12) Sri K. Thomas Jacob, Cochin Shiping Co., Cochin (i) 1970-71, (ii) Rs. 1379993, (iii) Rs. 1570000, (iv) Rs. 21250, (v) Rs. 21250. (13) Thomas Jacob, Cochin Shipping Co., Cochin-1. (i) 1971-72, (ii) Rs. 1385908. (iii) Rs. 1521000, (iv) Rs. 29840, (v) Rs. 25578. (i) 1972-73, (ii) Rs. 1402200, (iii) Rs. 1507770, (iv) Rs. 30616, (v) Rs. 27066 (i) 1973-74 (ii) Rs. 1391533 (iii) Rs. 1396300, (iv) Rs. 26889, (v) Rs. 26746. (14) V. Velayudhan Thampi, Vadaseri Amma Veedu, Perunthanni, Trivandrum, (i) 1973-74, (ii) Rs. 1266000, (iii) Rs. 1213000, (iv) Rs. 57187, (v) Rs. 57187.

[C. No. 188-B/TECH/75-76]

R. SREEKANTAN NAIR, Income-tax Officer,

(H. Qrs-II)

For Commissioner of Income-tax, Kerala-I & II.

समाहर्ता कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मद्रास

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

मद्रास, 1 सितम्बर, 1975

का० आ० 1095.—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5 वें नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा, मद्रास और कोयम्बतूर में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप-समाहर्ताओं को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944, के नियम 173छ (4) के अन्तर्गत समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का प्राधिकार प्रदान करता हूं।

[सी० सं०-IV/16/391/62-के० उ० III]

सी० चिदम्बरम्, समाहर्ता

THE MADRAS CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Madras, the 1st September, 1975

CENTRAL EXCISES

S.O. 1095.—In exercise of the powers conferred on me under rule 5 of the Central Excise Rules 1944, I hereby authorise the Deputy Collectors of Central Excise, Madras and Coimbatore to exercise the powers of Collector under rule 173 G(4) of the Central Excise Rules 1944.

[C. No. IV/16/391/62 CX. III]

C. CHIDAMBARAM, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1976

का० आ० 1096.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूती वस्त्र (नियन्त्रण) आदेश, 1948 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम सूती वस्त्र (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1976 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. सूती वस्त्र (नियन्त्रण) आदेश, 1948 के खण्ड 21 क में—

(i) उपखण्ड (1) और (2) में, "खण्ड 20 के उपखण्ड (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "खण्ड 20 के उपखण्ड (1) के परन्तुक" शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(2) विद्यमान उप खण्ड (3) को उपखण्ड (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड (4) के पूर्व निम्नलिखित उपखण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) जहां, किसी ऐसे उत्पादक के, जिसका कताई सयंत्र है या ऐसे उत्पादकों के समूह के आवेदन करने पर या अन्यथा, वस्त्र आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि इस खण्ड के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से किसी ऐसे उत्पादक या ऐसे उत्पादकों के समूह को अनुचित रूप से कष्ट या कठिनाई होती है तो वह आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे निदेश दे सकेगा कि वह निदेश ऐसे उत्पादक या ऐसे उत्पादकों के समूह को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए ।"

[फा० सं० 6/12/75 वस्त्र I]

दौलत राम, उप-सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 1976

S.O. 1096.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely :—

1. (1) This Order may be called the Cotton Textiles (Control) Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the clause 21A of the Cotton Textiles (Control) Order 1948—

(i) in sub-clauses (1) and (2), for the words, brackets and figures "sub-clause (2) of clause 20", the words, brackets and figures "the proviso to sub-clause (1) of clause 20" shall be substituted ;

(ii) the existing sub-clause (3) shall be re-numbered as sub-clause (4) and before sub-clause (4) as so re-numbered, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(3) Where, on an application made by any producer having spinning plant or group of such producers or otherwise, the Textile Commissioner is satisfied that any direction issued by him under this clause causes undue hardship or difficulty to any such producer or group of such producers he may, by order and for reasons to be recorded in writing, direct that the direction shall not apply, or shall apply subject to such modifications as may be specified in the order, to such producer or group of such producers."

[F. No. 6/12/75-Tex I]

DAULAT RAM, Dy. Secy.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1975

का० आ० 1097.—सर्वश्री जेनिथ इलेक्ट्रिकल्स आफ इंडिया, ई-29 इन्डस्ट्रियल एरिया, सोनीपत हरियाणा को केवल क्लास-ई और दूसरे उच्चतर ताप रोधक सामग्री और विद्युत वर्ग के आफ्ट कागज का आयात करने के लिए दो लाइसेंस संख्या पी०एल०/1808644 दिनांक 16-8-74 37136 रुपए के लिए और पी०/एस०/1808647 दिनांक 16-8-74 38130 रुपए के लिए प्रदान किए गये थे । उन्होंने उक्त लाइसेंसों और उनके लिए प्राधिकार पत्र सर्वश्री टेकनो ट्रेड, इंजीनियरिंग कंपनी कलकत्ता और सर्वश्री सनराईज इलैक्ट्रिक कारपोरेशन बम्बई के नाम में जारी किये गये को रद्द करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि प्राधिकार पत्र धारक उपलब्ध नहीं हैं ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि विषयाधीन लाइसेंस जिस प्रयोजन के लिए जारी किये गये थे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे । अब तक यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सी०सी) के अन्तर्गत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर लाइसेंस संख्या पी/एस/1808614 और पी/एस/1808647 दिनांक 16-8-74 की सीमाशुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रक प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं ।

[संख्या पी/जैड 7(एन)/ए एम 74/ए यू एच एच/सी एल ए]

के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS (CENRAL LICENSING AREA)

New Delhi, the 23rd October, 1975

CANCELLATION ORDER

S.O. 1097.—M/s. Zanith Electricals of India, E-29, Industrial Area, Sonepat, Haryana were granted import licences Nos. P/S/1808644 dated 16-8-74 for Rs. 37136 and P/S/1808647 dated 16-8-74 for Rs. 38130 both for import of class-E and other Higher Temperature Resisting materials and Electrical grade Kraft Paper only. They have requested for cancellation of the said licences and letter of authorities issued in favour of M/s. Techno Trade Engineering Co., Calcutta and M/s. Sunrise Electric Corporation Bombay against the same, on the ground that the L/A holders are not traceable.

In exercise of the powers conferred on me under clause 9(CC) Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-55 as amended up-to-date, I am satisfied that the licences in question will not serve the purpose for which these licences were issued and accordingly, I order the cancellation of customs purposes copies and exchange control purposes copies of the licences Nos. P/S/1808644 and P/S/1808647 dated 16-8-74.

[No. P/Z-7(N)/AM-74/AU-HH/CLA]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1976

रद्द करने का आदेश

का० आ० 1098.—सर्वश्री पी० मलपुरावाला एंड संस, एम० एम० बी० का रास्ता, जयपुर को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से बहुमूल्य/अर्ध-बहुमूल्य पत्थर आयात करने के लिए 11,789/- रुपए के लिए आयात लाइसेंस संख्या: पी० एल०/2634877/सी०एक्स० एक्स/50/डी०/37.38, एस० 3.4, दिनांक 12-3-74 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (केवल सीमाशुल्क निकासी तथा मुद्रा विनिमय प्रतियों के लिए) इस आधार पर आवेदन किया है कि उस लाइसेंस की मूल प्रतियां खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है । आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस उपयोग में नहीं लाया गया है ।

आवेदक ने उपर्युक्त कथन के समर्थन में कि लाइसेंस (सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय प्रतियां) अस्थानस्थ हो गया है, आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक 1975-76 के पैरा 320 के अनुसार एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है ।

आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी० सी०) के अधीन मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं 11,789 रुपए के लिए उक्त लाइसेंस संख्या : पी० एल/2624877, दिनांक 12-3-1974 की मूल सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं ।

अब हैंडबुक, क्रियाविधि, 1975-76 के पैरा 320(4) की व्यवस्थाओं के अनुसार आवेदक को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए 11,789/-रुपये के लिए उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क एवं मुद्रा विनिमय की प्रतियां जारी की जा रही है ।

[संख्या: जेम० 149/ओडी-73/एस सी०-5/सी एच क्यू]

एच० एल० बहल, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

New Delhi, the 16th January, 1976

CANCELLATION ORDER

S.O. 1098.—M/s. P. Malpurawala & Sons, M. S. B. Ka Rasta, Jaipur were granted import licence No. P/L/2634877/C/XX/50/D/37.38, S. 3.4 dated 12-3-74 for Rs. 11789 for import of Precious/Semi Precious Stones & Uncut & Unset for G. C. A. They have applied for duplicate copy (Customs & Exchange copies only) of the said licence on the ground that original copies of the same have been lost/misplaced. It is further stated that the licence have not been utilised.

The applicant has filed an affidavit in support of their above statement about the misplacement of the licence (Customs & Exchange copies) as required under para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure 1975-76. I am satisfied that original Custom copy and Exchange copy of the above licence has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under Section 9(CC) Import Control Orders, 1955 dated 7-12-55. I order the cancellation of Original Customs & Exchange copies of the above licence No. P/L/2634877/C/XX/50/D/37.38, S. 3.4 dated 12-3-74 for Rs. 11789.

The applicant is now being issued duplicate Customs & Exchange copies of the aforesaid licence for Rs. 11789 on G.C.A. in accordance with the provision of Para 320(4) of the Hand Book of Rules & Procedures 1975-76.

[F. No. Gem. 149/OD. 73/SC. IV/CLA]

H. L. BAHAL, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

आदेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1976

का० आ० 1099.—सर्वश्री हैज गोल्य लि०, श्री शाइले, कनकपुरा रोड, बंगलौर को रुपये में भुगतान के आधार पर भारत-जर्मन प्रजातन्त्र गणराज्य व्यापार योजना व्यवस्था के प्रति 1,33,000/- रुपए लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए आयात लाइसेंस संख्या: पी/सी/2068293/टीई जी/48/एच/37-38/सी जी-4, दिनांक 12-9-1973 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बैंकर के पास पंजीकृत कराए बिना ही अस्थानस्थ हो गई/खो गई है ।

उपर्युक्त के समर्थन में आवेदक ने बंगलौर नगर के नौटरी के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उक्त लाइसेंस के संबंधित संलग्नों के साथ अस्थानस्थ हो गई/खो गई है । इसलिए, आयात (नियंत्रण), आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री हैज एंड गोल्य लि० को जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या : पी/सी/2068293/टी/ईजी/48/एच/37-38/सी जी- 4 दिनांक 12-9-1973 की उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है ।

आवेदक को उक्त आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या 13(13)/73-74/सी-जी/4]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

ORDER

New Delhi, the 20th January, 1976

S.O. 1099.—M/s. Hegda and Golay Ltd., Shreeshyla, Kanakpura Road, Bangalore were granted import licence No. P/C/2068293/T/EG/48/H/37.38/CG.IV dated 12-9-1973 for the cif value of Rs. 1,33,000 on Rupee Payment Basis against Indo-GDR Trade Plan Provisions. They have applied for issue of a duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said import licence on the ground that the original Exchange Control Purposes Copy has been misplaced/lost. without being registered with the Bankers.

2. In support of the above the applicant has filed an affidavit duly sworn before a Notary, Bangalore City. I am accordingly satisfied that the Original Exchange Control Purposes Copy with relevant enclosures of the said Import Licence has been misplaced/lost. Therefore, in exercise of the powers delegated under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Exchange Control Purposes Copy of the import licence No. P/O/2068293/T/EG/48/H/37.38/CG. IV dated 12-9-1973 issued to M/s. Hedge and Golay is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said Import Licence is being issued to the applicant separately.

[No. 13(13) 73-74/CGIV]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

for Chief Controller of Imports & Exports.

ORDER

New Delhi, the 30th January, 1976

S.O. 1100.—M/s. Hindustan Shipyards Limited, P.O. Gandhigram, Visakhapatnam, were granted an import licence No. G/A/1029412/O/XX/23/C/H/23 dated 17-10-66 for Rs. 1,12,42,844 (Rupees one crore twelve lakhs forty two thousand eight hundred & forty four only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes/Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes/Exchange Control Purposes copy been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes/Exchange Control copy was registered with the Customs authorities/ at Bank Ltd., unutilised and utilised fully/partly. It was utilised for Rs. 91,02,594.69 and the balance available on it was Rs. 21,40,249.31 as on 18-4-1975.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Notary I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes/Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. G/AU/1029412/C/XX/23/C/H/23 dated 17-10-66 issued to M/s. Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. Part F. No. RP/POL/24/66-67/LI(B)/PLS(A)]

आदेश

नई दिल्ली 30 जनवरी, 1976

का० आ० 1100.—सर्वश्री हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० पी० ओ० गांधीग्राम, विशाखापत्तनम को 1,12,42,844 रुपये (एक करोड़ बारह लाख बयालीस हजार, आठ सौ चवालीस रुपए मात्र के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या जी/ए/1029412/सी/एक्स/एक्स/23/सी/एच/23, दिनांक 17-10-1966 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेन्स की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। इसका उपयोग 91,02,594,69 रुपए के लिए किया गया था और दिनांक 18-4-1975 को इसमें 21,40,249.31 रुपया शेष था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक नोटरी के प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सीसी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंस संख्या जी०/ए०यू०/1029412/सी/एक्स एक्स/23 दिनांक 17-10-66 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या पार्ट फाइल नं० आर० पी०/पाल/24/66-67/एल आई (बी)/पी० एस० (ए)]

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

का० आ० 1101.—सर्वश्री भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० हरिद्वार (उ०प्र०) को 3,00,00,000/- रुपये (तीन करोड़ रुपया मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या आई/ए/1404668/टी०/यू०आर० ई 53/एच/39-40, दिनांक 8-10-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है।

इसका उपयोग 1,02,79,563.37 रुपए के लिए किया गया था तथा दिनांक 9-1-1976 को इसमें शेष 1,97,20,436.63 रुपए उपलब्ध था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने स्थानीय मैजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा प्रमाण-पत्र सहित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उक्त लाइसेंस संख्या: आई०-ए०/1404668 दिनांक 8-10-74 जो कि सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि०, हरिद्वार को जारी किया गया था, उसकी मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द कर दी गई है।

लाइसेंस धारी को उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० एचईएल/11/74-75/पीएलएस(ए)]

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1976

S.O. 1101.—M/s. Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar (U.P.) were granted an import licence No. I/A/1404668/T/UR/53/H/39.40 dated 8-10-74 for Rs. 3,00,00,000

(Rupees Three Crores Only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes copy has been lost.

It was utilised for Rs. 1,02,79,563.37 and the balance available on it was Rs. 1,97,20,436.63 as on 9-1-1976.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Resident Magistrate, Hardwar. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-55 as amended the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. I/A/1404668 dated 8-10-74 issued to M/s. Bharat Heavy Electrical Limited Hardwar, is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. HEL/11/74-75/PLS(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1976

का० आ० 1102.—सर्वश्री भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल को 60,00,000 (साठ लाख रुपए मात्र) रुपयों के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या आई/डी/1409606/एस/एम०एल/55/एच/41-42, दिनांक 17-5-75 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति बम्बई में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत थी और आंशिक रूप से उपयोग में लाई गई थी। वह 1,64,266 रुपए के लिए उपयोग में लाई गई थी और 7-11-75 को उस पर उपलब्ध धन राशि 58,35,734 रुपए शेष थी।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने उप पंजीयक, महानगरीय मजिस्ट्रेट बम्बई के एक प्रमाण-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए, यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल को जारी किए गए लाइसेंस संख्या आई/डी/1409606/एस/एम० एल०/55/एच/41-42, दिनांक 17-5-75 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सेन्ट/एच ई एल/23/71-72/पी एल एस(ए)]

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1976

S.O. 1102.—M/s. Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal were granted an import licence No. I/D/1409606/S/ML/55/41-42, dated 17-5-75 for Rs. 60,00,000 (Rupees sixty lakhs only). They have applied for the issue a duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes Copy was registered with the Custom Authorities at Bombay and utilised partly.

It was utilised for Rs. 1,64,266 and the balance available on it was Rs. 58,35,734 as on 7-11-75.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit alongwith a certificate from Deputy Registrar, Metropolitan Magistrate Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-55 as amended the said original Customs Purposes copy of the licence No. I/D/1409606/S/ML/55/LH/41-42, dated 17-5-75 issued to M/s. Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. Cent./HEL/23/71-72/PLS(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

का० आ० 1103.—सर्वश्री खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम लि०, पो० ओ० दुर्गापुर-713210 जि० बुर्दवान, पश्चिमी बंगाल को 12,12,000 रुपया (बारह लाख तथा बारह हजार रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस संख्या आई/ए/1406594/टी/ओ आर/54/एच/39-40, दिनांक 17-1-75 प्रदान किया गया था। इन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा-शुल्क प्राधिकारी कलकत्ता के पास पंजीकृत कराई गई थी तथा उसका आंशिक रूप से उपयोग किया गया था। इसका उपयोग 59,812 रुपए के लिए किया गया था और दिनांक 3-12-75 को इसमें शेष 11,52,188 रुपए उपलब्ध था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने श्री एन०जी० दत्त, नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाण-पत्र सहित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12 1955 की उप-धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम लि०, पी० ओ० दुर्गापुर, जि० बुर्दवान, पश्चिमी बंगाल को जारी किए गए उक्त लाइसेंस संख्या आई/ए/1406594/टी/ओ आर/54/एच/39-40, दिनांक 17-1-75 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० एच ए एम/3/74-75/पी एल एस (ए)]

ओ० एन० आनन्द, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1103.—M/s. Mining and Allied Machinery Corporation Limited, P. O. Durgapur-713210, Dt. Burdwan, West Bengal were granted an import licence No. I/A/1406594/T/OR/54/H/39-40, dated 17-1-75 for Rs. 12,12,000 (Rupees Twelve lakhs and Twelve thousand only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been misplaced. It is further stated that the original Customs copy was registered with the Customs Authorities at Calcutta and utilised partly. It was utilised for Rs. 59,812 and the balance available on it was Rs. 11,52,188 as on 3-12-75.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Shri N. G. Datta, Notary Public. I am accordingly satisfied that the original

Custom Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955, dated 7-12-55 as amended the said original Custom Purposes copy of licence No. I/A/1406594/T/OR/54/H/39-40, dated, 17-1-1975 issued to M/s. Mining & Allied Machinery Corporation Limited., P.O. Durgapur, Dt. Burdwan, West Bengal is hereby cancelled.

3. A duplicate Custom Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. H/AM/3/74-75/PLS(A)]

O. N. ANAND, Dy. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक,आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

मद्रास, 7 जनवरी, 1976

का० आ० 1104.—सर्वश्री मोहनलाल बागमल, 107/109 न्यनिप्पा नायक स्ट्रीट, मद्रास-3 को अप्रैल/मार्च, 1976 की अवधि के लिए औषधि तथा दवाइयां क्रम संख्या 87-109/4 का आयात करने के लिए 13,177/- रुपये के लिए संख्या पी/ई/0244284, दिनांक 21-10-75 प्रदान किया गया था ।

2. फर्म ने उपयुक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्राप्त करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति बिकुल उपयोग में लाए बिना ही अस्थानस्थ हो गई है अथवा खो गई है । इस विषय में उन्होंने इस कार्यालय को एक शपथ-पत्र भी दाखिल किया है ।

3. मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की मूल प्रति अस्थानस्थ अथवा खो गई है और मैं निदेश देता हूं कि फर्म को मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की एक अनुलिपि जारी की जानी चाहिए । उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति की मूल प्रति रद्द की जाती है ।

(सिमिल संख्या : 87-109/4/494 ए०एम०-76/ई-1 से जारी)

[सं० 87-109/IV/494/ए० एम-76]

आर० कुमारवेलु, उपमुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य नियंत्रक

Office of the Jt. Chief Controller of Imports Exports

ORDER

Madras, the 7th January, 1976

S.O. 1104.—M/s. Mohanlal Bagmal, 107/109, Nyniappa Naick St. Madras-3 were granted a licence No. P/E/0244284/C/XX/57/M/41-42 dated 21-10-75 for Rs. 13177 (Rupees thirteen thousand one hundred and seventy seven only) by this office for import of Drugs and Medicines, S. No. 87-109/IV for the period of April-March 1976.

The firm have now applied for grant of duplicate copy of Exchange Control Copy of the above licence on the ground that the original has been misplaced/lost without having been utilised at all. They have also filed an affidavit in this regard with this office.

I am satisfied that the original copy of the Exchange Control copy of the licence has been misplaced/lost and I direct that a duplicate of the Exchange Control copy of the licence should be issued to the firm. The original copy of Exchange Control Copy of the licence mentioned above is cancelled.

[Issued from file No. 87-109/IV/494/AM-76/EI]

R. KUMARAVELU, Dy. Chief Controller
For Chief Controller.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1976

का० आ० 1105.—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री डी० पी० सिंहानिया के स्थान पर श्री गुरबचन सिंह आनन्द को 12 दिसम्बर, 1975 से मोटरगाड़ियों, मोटरगाड़ी सहायक उद्योगों, परिवहन यान उद्योगों, ट्रैक्टरों मिट्टी हटाने के उपकरण तथा इंटरनल कम्बश्चन इंजनों के विनिर्माण तथा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के, तत्पश्चात् यथा संशोधित, आदेश सं० का० आ० 116-आई० डी० आर० ए/6/16, तारीख 1 जनवरी, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में, क्रम सं० 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, अर्थात:—

"21 श्री गुरबचन सिंह आनन्द, अध्यक्ष,

फैडरेशन आफ आल इंडिया आटोमोबाइल्स स्पेयर पार्टस डीलर्स एसोसिएशन,

3620/21, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली-110006

[फा०सं० 15(5)/74-ए०ई०आई (1)]

वी०पी० गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 4th March, 1976

S.O. 1105.—In exercise of the powers conferred by sections 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints with effect from the 12th December, 1975, Shri Gurbachan Singh Anand vice Shri D. P. Singhania, to be a member of the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture and production of Automobiles, Automobile Ancillary Industries, Transport Vehicles Industries, Tractors, Earth Moving Equipment and Internal Combustion Engines, and makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. S.O. 116-IDRA/6/16 dated the 1st January, 1975 as amended subsequently, namely :—

In the said Order, for serial No. 21 and the entries relating thereto, the following serial No. shall be substituted, namely :—

"21 Shri Gurbachan Singh Anand, President, Federation of All India Automobile Spare Parts Dealers' Association, 3620/21, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, Delhi-110006."

[F. No. 15(5)/74-AEI(I)]

V. P. GUPTA, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

का० आ० 1106.—तत्कालीन औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा कंपनी मामलों के मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4308 दिनांक 9 अक्टूबर 1969 जिसके द्वारे भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 25 अक्टूबर 1969 में छपे थे, को अधिक्रमित करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि रबड़ कैनवस के खनिकों के बचाव बूटों से संबंधित मानक चिन्ह का पुनरीक्षण किया गया है। इस मानक चिन्ह की पुनरीक्षित डिजाइन तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित और उसके शाब्दिक विवरण के साथ नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिन्ह 27 नवम्बर, 1975 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1.	IS : 3976 Part I IS: 3976 Part II	रबड़ कैनवस के खनिकों के बचाव बूट	IS : 3976-1975 रबड़ कैनवस के खनिकों के बचाव बूटों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या तथा मोनोग्राम के नीचे की ओर टाइप पदनाम अर्थात् "टाइप 1" और "टाइप 2" अंकित हैं।

[संख्या सी०एम० डी०/13 : 9]

(Department of Industrial Development)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 16th February, 1976

S.O. 1106.—In supersession of the then Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) (Indian Standards Institution) notification number S.O. 4308 dated 9 October 1969, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 25 October 1969, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark for safety rubber canvas boots for miners has been revised. The revised designs of the Standard Marks together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the designs are given in the following Schedule.

These standard Marks for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulation framed thereunder, shall come into force with effect from 27 November 1975.

SCHEDULE

Sl No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS:3976 Part I IS : 3976 Part II	Safety rubber-canvas boots for miners	IS : 3976-1975 Specification for Safety rubber canvas boots for miners (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution consisting of letter 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the type designation namely 'Type I' & 'Type II' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the designs.

157 GI/75—3. [No. CMD/13:9]

का० आ० 1107.— भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है और प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लिखने और छपाई का कागज	IS : 1848-1971 लिखने और छपाई के कागज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 2.00	1 अक्टूबर 1975
2.	आगे पीछे होने वाला स्प्रेअर	IS : 3062-1970 आगे पीछे होने वाले स्प्रेअर की विशिष्टि	एक मद	50 पैसे	1 दिसम्बर 1971

[संख्या सी० एम० डी०/13 : 10]

S.O. 1107.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Writing and printing papers . .	IS:1848-1971 Specification for writing and printing papers (first revision)	One Tonne	Rs. 2.00	1 Oct. 1975
2.	Rocker Sprayer	IS:3062-1970 Specification for rocker sprayer (first revision)	One piece	50 Paise	1 Dec. 1971

[No. CMD/13: 10]

का० आ० 1108.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गर्म हवा का पंखा	IS : 4283-1967 गर्म हवा के पंखे की विशिष्टि	एक पंखा	रु० 1.00	1 नवम्बर 1975
2.	मशीनी कार्यों के लिए चमकदार इस्पात की छड़ें	IS : 4855-1968 मशीनी कार्यों के लिए चमकदार इस्पात की छड़ों की विशिष्टि	एक मीटरी टन	50 पैसे	16 नवम्बर 1975

[संख्या सी० एम० डी०/13 : 10]

S.O 1108.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee (s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hot air fan	IS:4283-1967 Specification for hot air fan	One fan	Re. 1.00	1 Nov. 1975
2.	Bright steel bars for machining .	IS:4855-1968 Specification for bright steel bars for machining	One Tonne	50 Paise	16 Nov. 1975

[No. CMD/13:10]

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1976

का०आ० 1109.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह्) विनियम 1955 के विनियम 3 के उप-विनियम (4) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अनुसार, IS:1786-1966 के उपबंधों में कुछ संशोधन जिनके ब्यौरे अनुसूची में दिए हैं, मानक चिन्ह् के उपयोग में गति लाने के परीक्षात्मक रूप में किए गए हैं। इन संशोधनों से भारतीय मानक के अनुरूप माल की गुणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये संशोधन तुरन्त ही लागू हो जाएंगे।

अनुसूची

क्रम सं०	भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक जिसके उपबंधों में संशोधन किए गए हैं।	भारतीय मानक के उपबंधों में किए गए संशोधनों का विवरण
1	2	3
1.	IS: 1786-1966 कंक्रीट प्रबलन के लिए शीत मरोड़ी इस्पात की सरिया की विशिष्टि. (पुनरीक्षित)	वर्तमान खंण्ड 9.1.3 के स्थान पर निम्नलिखित कर दीजिए "9.1.3 खण्ड 9.1.1 और खण्ड 9.1.2 के अनुसार लिए गए परीक्षण नमूने वेल्लित और तत्पश्चात् शीत मरोड़ी सरिये की पूर्ण काट होंगे और उनमें और कोई परिवर्तन किए बिना उन पर भौतिक परीक्षण किए जाएंगे। मशीन करने अथवा अन्य किसी प्रकार से उसके साइज में कमी नहीं आने दी जाएगी केवल 28 मिमी और उससे ऊपर के सरियों को छोड़कर (देखिए खंण्ड 9.1.3.1) किसी भी परीक्षण नमूने का ऋणशीतलन नहीं किया जाए। अगर किसी परीक्षण नमूने को सीधा करना हो तो उसे ठंडे ही सीधा किया जाए। 9.1.3.1 व्यास में 28 मिमी और इससे ऊपर के सरियों पर तनाव सामर्थ्य प्रमाणक प्रतिबल और प्रलम्बन प्रतिशत सम्बन्धी परीक्षण करने हों तो सरिया में उपरी लकीरों आदि को मशीन कर लिया जाए।"

[सं० सी०एम०डी०/13 : 4]

बी०एस० कृष्णमाचारी, महानिदेशक

New Delhi, the 1st March, 1976

S.O. 1109.—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of IS : 1786-1966, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This notification shall come into force with immediate effect.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard the Provisions of which have been modified	Particulars of the Modifications made to the provisions
1	2	3
1.	IS : 1786—1966 Specification for cold twisted steel bars for concrete reinforcement (revised).	Substitute the following for the existing clause 9.1.3 : "9.1.3 The test pieces obtained in accordance with clause 9.1.1 and clause 9.1.2 shall be full sections of the bars as rolled and subsequently cold worked and shall be subjected to physical tests without any further modifications. No reduction in size by machining or otherwise shall be permissible, except in case of bars of size 28 mm and above (*see* clause 9.1.3.1). No test piece shall be annealed or otherwise) subjected to heat treatment. Any straightening which a test piece may require shall be done cold. 9.1.3.1 For the purpose of carrying out tests for tensile strength, proof stress and percentage elongation for bars 28 mm in diameter and above, ribs of the bars may be machined."

[No. CMD/13 : 4]

B.S. KRISHNAMACHARI, Dir. Gen.

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1110.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 5136 dated the 15th November, 1975, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 6th December, 1975 at pages 4190 and 4191—

(i) at page 4190 in para 2 line 2—

FOR 'Coal Collector',

READ 'Coal Controller'

(ii) at page 4191 in the SCHEDULE, against Serial Number 3, below Tehsil Number—

FOR '283'

READ '288'

[No. C5-4(15)/74/CEL]

S. R. A. RIZVI, Dy. Secy

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1976

का० आ० 1111.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उप-धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है ; और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1976 है ;

2. विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खण्ड 37 में, उप-खण्ड (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) रजिस्ट्रीकृत नियोजक किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को, उस कर्मकार को प्रसामान्यतः और वस्तुतः देय मजदूरी से अधिक नकद या अन्यथा किसी भी चीज का संदाय नहीं करेगा।"

[सं० एल डी वी/36/75]

वी० संकालिंगम, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th February, 1976

S.O. 1111.—The following draft of a scheme further to amend the Viskhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This scheme may be called the Viskhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1976;

2. In Clause 37 of the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1959, after sub-clause (6) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(7) A registered employer shall not pay a registered dock worker anything in cash or otherwise in excess of the wages normally and actually due to the workers."

[No. LDV/36/75]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

का० आ० 1112.—संविधान की धारा 148 के खण्ड (5) तथा धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के बारे में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मेरठ) नियमावली, 1971 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; नामत :-

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मेरठ) संशोधन नियमावली, 1976 कहे जायें।

   (2) यह नियम 1 फरवरी, 1976 से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मेरठ) नियमावली, 1971 में नियम 1 उपनियम (3) में खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा ; नामत :—

"(1) मेरठ में ऐसे क्षेत्र तथा इससे संबद्ध ऐसे क्षेत्र जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर जारी सरकारी राजपत्र में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे"।

[संख्या एफ० 3-26/75-के० स० स्वा० यो०]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O. 1112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules to amend the Central Government Health Scheme (Meerut) Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Government Health Scheme (Merrut) amendment rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st February, 1976.

2. In the Central Government Health Scheme (Meerut) Rules 1971 in rule 1, in sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :

"(i) such areas in Meerut, and such areas contiguous thereto, as the Central Government may, from time to time, by order in the Official Gazette, specify".

[No. F. 3-26/75-CGHS]

का० आ० 1113.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मेरठ) नियमावली, 1971 के नियम 1 के उप-नियम (3) के खण्ड (1) तथा इस संबंध में सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त नियमावली को 1 फरवरी, 1976 से मेरठ के निम्नलिखित क्षेत्रों तथा इनके समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू करती है; नामत :—

कांकर खेरा औषधालय (सं० 4)

इस औषधालय का क्षेत्र कांकर खेरा नगरपालिका की सीमाओं तक सीमित होगा, जो इस प्रकार है —

पूर्व में रेलवे ग्राउण्ड की दीवार, नाला तथा रेलवे लाइन, पश्चिम में पी० सी० एफ० वर्कशाप के पीछे का रास्ता जो उत्तर से दक्षिण तक आबू नाला तक जाता है, उत्तर में सरधना रोड, दक्षिण में आबू नाला ।

[संख्या एफ० 3-26/75-के० स० स्वा० यो०]

वि० रामचन्द्रन, अवर सचिव

S.O. 1113.—In pursuance of clause (i) of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Meerut) Rules, 1971 and all other powers here-unto enabling, the Central Government hereby extends the said rules with effect from the 1st February, 1976 to the following areas in Meerut and areas contiguous thereto, namely :—

Kankar Khera Dispensary (No. 4)

The area of this Dispensary shall be confined to the limits of Town Area Kankar Khera, which is as under :

In the East, wall of Railway Ground, Nalla and Railway line; in the West the path behind the P.C.F. workshop, which runs North to South up to Abu Nalla; in the North Sardhana Road; in the South Abu Nalla.

[No. F. 3-26/75-CGHS]

V. RAMACHANDRAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1976

का० आ० 1114.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 27 मार्च, 1976 की अधिसूचना सं० 16-15/61-चि० I द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए वैलेन्सिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त एल० एम० एस० मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ;

और यतः डा० एंजील्स एर्सिल्ला विजकारा जिसके पास उक्त अर्हता है शिक्षण अनुसंधान तथा धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल नाजरेठ हास्पिटल लैटुमखराह, शिलांग, मेघालय के साथ सम्बद्ध हैं ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा —

(1) इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि ;

अथवा

(2) इस अवधि को जब तक डा० एंजील्स एर्सिल्ला विजकारा नाजरेठ हास्पिटल लैटुमखराह, शिलांग, मेघालय के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे ।

[सं० वी० 11016/3/76-एम० पी० डी०]

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1976

S.O. 1114.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning No. 16-15/61-MI, dated the 27th March, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualifications, "L.M.S." granted by the Valencia University, Spain shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Angles Ercilla Vizcarra who possesses the said qualification is for the time being attached to the Nazareth Hospital Laitumkhrah, Shillong, Meghalaya for the purposes of teaching, research and charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette; or

(ii) the period during which Dr. Angles Ercilla Vizcarra is attached to the said Nazareth Hospital, Laitumkhrah, Shillong, Meghalaya,

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/3/76-MPT]

आदेश

का० आ० 1115.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 30 दिसम्बर, 1960 की अधिसूचना सं० 16-18/60 चि० I द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए मन्स्टर विश्वविद्यालय, पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्रदत्त एम० डी० (मन्स्टर) मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ;

और यतः डा० अगस्त-आटो बीन को जिसके पास उक्त अर्हता है शिक्षण अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल डैमिन (कुष्ठ) संस्थान, कोझुकुल्ली, पो० 68078, त्रिचुर-5 के साथ सम्बद्ध है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि ;

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० अगस्त-ओटो बीन डैमीन (कुष्ठ) संस्थान, कोझुकुल्ली, त्रिचुर-5 के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे ।

[सं० बी० 11016/1/76-एम० पी० टी०]

ORDER

S.O. 1115.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-18/60-MI dated the 30th December, 1960, the Central Government has directed that the medical qualifications, "M.D, (Munster)" granted by the Universtiy of Munster, West Germany, shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. August—Otto Beine, who possesses the said qualification is for the time being attached to the Damien (Leprosy) Institute, Kozhukully, P.O.-68078, Trichur-5 (Kerala), for the purposes of teaching, research charitable works:

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. August—Otto Beine is attached to the said Damien (Leprosy) Institute, Kozhukully, Trichur-5

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/1/76-MPT]

आदेश

का० आ० 1116.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 जुलाई, 1962 अधिसूचना सं० 16-5/62-चि० I द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए जार्ज टाउन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदत्त एम० डी० मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ;

और यतः डा० एलीन नीडफील्ड जिसके पास उक्त अर्हता है शिक्षण अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल होली फेमिली अस्पताल, मन्डार, रांची जिला बिहार के साथ सम्बद्ध है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) 31 दिसम्बर, 1976 तक की अवधि;

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० एलीन नीडफील्ड होली फेमिली अस्पताल, मन्डार, रांची जिला बिहार के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे ।

[सं० बी० 11016/4/76-एम० पी० टी०]

विवेक कुमार अग्निहोत्री, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1116.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning No. 16-5/62-MI dated the 23rd July 1962, the Central Government has directed that the Medical qualifications, "M.D." granted by the University of Georgetown, Washington, U.S.A. shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Eileen Niedfield who possesses the said qualification is for the time being attached to the Holy Family Hospital, Mandar, Ranchi District, Bihar, for the purposes of teaching, research and charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period up to the 31st December, 1976 or

(ii) the period during which Dr. Eilen Niedfield is attached to the said Holy Family Hospital, Mandar, Ranchi District, Bihar

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/4/76-MPT]

V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1976

का०आ० 1117.—अतः कतिपय संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, इसके उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित क्षेत्र के सम्बन्ध में दिल्ली की क्षेत्रीय विकास प्लान में करने की प्रस्तावना करती है, दिल्ली विकास (मास्टर प्लान तथा क्षेत्रीय विकास प्लान नियम, 1959 तथा इसके नियम 6 और दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में दिनांक 26 अप्रैल, 1975 की सूचना संख्या फा० 3(212)/72 एम०पी० के रूप में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा प्रस्तावित उपान्तरण के बारे में जनता से आक्षेप और सुझाव उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में मांगे गए थे जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) में अपेक्षित है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली की क्षेत्रीय विकास प्लान में संशोधन करने का निर्णय किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की उक्त क्षेत्रीय विकास प्लान में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्, :—

उत्तर में ओखला गांव, पूर्व और पश्चिम में मनोरंजनात्मक क्षेत्र तथा दक्षिण में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्रीय विकास प्लान नं एफ 1 तथा एफ 7 से शिक्षा और अनुसंधान सांस्थानिक प्रयोग के लिए उद्दिष्ट लगभग 3.9 हैक्टेयर (9.7 एकड़) के क्षेत्र को "शिक्षा और अनुशासन सांस्थानिक प्रयोग से" "रिहायशी प्रयोग" के लिए परिवर्तित किया जाता है ।

अनुसूची

उत्तर में ओखला गांव, पूर्व और पश्चिम में मनोरंजनात्मक क्षेत्र तथा दक्षिण में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र से घिरा हुआ लगभग 3.9 हैक्टेयर (9.7 एकड़) का क्षेत्र ।

[सं० के० 13011/4/यु०डी० I]

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 9th March, 1976

S.O. 1117.—Whereas certain modification, which the Central Government proposed to make in the master plan for Delhi regarding the area mentioned in the Schedule annexed hereto, was published as notice No. F. 3(212)/72-M.P. dated the 26th April, 1975, in accordance with rule 16 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, read with rule 6 of the said rules and section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) in the Official Gazette and by advertisement in local newspaper, inviting objections and suggestions from any person with respect to the proposed modification within a period of thirty days from the date of the said notice, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act.

And whereas the Central Government, after considering the objections and suggestions received with respect to the proposed modification, have decided to modify the master plan for Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said master plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

An area measuring about 3.9 hectares (9.7 acres), surrounded by Okhla village in the north, recreational area in the east and west and public and semi-public facilities area in the south, earmarked for education and research institutional use in the master plan changed from "education and research institutional use" to "residential use".

SCHEDULE

An area measuring about 3.9 hectares (9.7 acres) surrounded by Okhla village in the north, recreational area on the east and west and public and semi-public facilities area in the south.

[No. K. 13011/4/74-UDI]

का०आ० 1118.—अतः कतिपय संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, इसके उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित क्षेत्र के सम्बन्ध में दिल्ली की क्षेत्रीय विकास प्लान में करने की प्रस्तावना करती है, दिल्ली विकास (मास्टर प्लान तथा क्षेत्रीय विकास प्लान नियम, 1959 तथा इसके नियम 6 और दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 क 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में दिनांक 26 अप्रैल, 1975 की सूचना संख्या फा० 3(212)/72-एम०पी० के रूप में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा प्रस्तावित उपान्तरण के बारे में जनता से आक्षेप और सुझाव उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में मांगे गए थे जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली की क्षेत्रीय विकास प्लान में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की उक्त क्षेत्रीय विकास प्लान में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्, :—

उत्तर में ओखला गांव, पूर्व और पश्चिम में मनोरंजनात्मक क्षेत्र तथा दक्षिण में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्रीय विकास प्लान सं० एफ-1 तथा एफ-7 में शिक्षा और अनुसंधान सांस्थानिक प्रयोग के लिए उद्दिष्ट लगभग 3.9 हैक्टेयर (9.7 एकड़) के क्षेत्र की "शिक्षा और अनुशासन सांस्थानिक प्रयोग से" "रिहायशी प्रयोग" के लिए परिवर्तित किया जाता है।

अनुसूची

उत्तर में ओखला गांव, पूर्व और पश्चिम में मनोरंजनात्मक क्षेत्र तथा दक्षिण में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र से घिरा हुआ लगभग 3.9 हैक्टेयर (9.7 एकड़) का क्षेत्र।

[सं० के० 13011/4/यू०डी० I]

पी०एस० रवीन्द्रा, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

S.O. 1118.—Whereas certain modification, which the Central Government proposed to make in the zonal development plan for Delhi regarding the area mentioned in the Schedule annexed hereto, was published as notice No. F. 3(212)/72-M.P. dated the 26th April, 1975, in accordance with rule 16 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, read with rule 6 of the said rules and section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) in the Official Gazette and by advertisement in local newspaper, inviting objections and suggestions, from any person with respect to the proposed modification; within a period of thirty days from the date of the said notice, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act;

And whereas the Central Government, after considering the objections and suggestions received with respect to the proposed modification, have decided to modify the zonal development plan for Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said zonal development plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

An area measuring about 3.9 hectares (9.7 acres), surrounded by Okhla village in the north, recreational area in the east and west and public and semi-public facilities area in the south, earmarked for education and research institutional use in the zonal development plan number F-1 and F-7 changed from "education and research institutional use" to "residential use".

SCHEDULE

An area measuring about 3.9 hectares (9.7 acres) surrounded by Okhla village in the north, recreational area on the east and west and public and semi-public facilities area in the south.

[No. K. 13011/4/74 UDI]

P. S. RAVINDRA, Section Officer (Spl.)

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1976

का०आ० 1119.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पालघर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/76/पी०एण्ड०बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 8th March, 1976

S.O. 1119.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated the 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-4-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Palghar Telephone Exchange, Maharashtra Circle.

[No. 5-4/76-PHB I

का० आ० 120.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने खंबालिया टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-76 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/76 पीए च बी]

पी०सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक

S.O. 1120.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated the 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-4-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Khambalia Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-11/76-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Dir. General

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1976

का० आ० 1121.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सेचलम्बरगर सीको (इन्क०) साउथ एशिया डिविजन, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० यू० शाह होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स सेचलम्बरगर सीको (इन्क०) साउथ एशिया डिवीजन, 6-डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र की श्री अगस्टाईन विन्सेण्ट, अकुशल कर्मकार को 9-11-1972 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-30012(4)/75-डी-4 (बी)]

भूपेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 6th January, 1976

S.O. 1121.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Schlumberger Seaco (Inc.) South Asia Division, New Delhi and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. U. Shah shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Schlumberger Seaco (Inc.) South Asia Division, 6-Defence Colony, New Delhi in terminating the services of Shri Augustine Vincent, Unskilled worker with effect from 9-11-1972 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-30012(4)/75-D-IV(B)]

S.O. 1122.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited, Post Office Mosaboni and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th March, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

REFERENCE NO. 50 OF 1975

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

ORDER OF REFERENCE

(Ministry's Order No. L-29011/35/74-LR-IV-D-IV(B) dt. 9-5-1975)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of M/s. Hindustan Copper Limited, P.O. Mosaboni.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the Employers—Shri A. K. Sarkar, Advocate.

On behalf of the workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Copper.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour sent this reference dated 9th May, 1975 to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed:

"(1) Whether the following demands of the workmen of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of M/s. Hindustan Copper Limited, P.O. Mosaboni are justified?

(2) If so, to what relief are the workmen entitled?"

DEMANDS

(1) Payment of attendance bonus to the monthly rated workers employed in underground, fulfilling the conditions for payment keeping in view clause II of the tripartite settlement dated the 29th December, 1969, and

(2) Employing Explosive checkers as Time Keeprs in addition to their duties as explosive checkers without payment of additional remuneration.

On receipt of the order of reference notices were issued to both the employers and the workmen. Parties appeared through their authorised representatives. After taking some time both sides filed their written statements. Some documents were also filed by the employers. The case proceeded along its course. It appears that on 25-11-75 when the case was fixed, the workmen were neither present nor any steps taken. Similarly on 26-12-75 when the case was fixed the workmen were neither present nor took any steps. I adjourned the case to 12-1-76 when the workmen were neither present nor took any steps. I had recorded an order that if the workmen continued to remain absent and failed to take any steps the case will be disposed of according to law. For affording another opportunity to the workmen the case was fixed for evidence and argument on 30-1-76. On 30-1-76 the employers represented by Shri A. K. Sarkar, Advocate and other officers appeared. None appeared for the workmen nor took any steps. It will therefore appear that since November 1975 the workmen remained absent without taking any steps on four successive occasions when the case was fixed. There was no indication that the workmen would be coming. Sri A. K. Sarkar, learned Advocate for the employers submits that the industrial dispute was raised by the workmen and the reference was also made at their instance. He submits that the employers position is that of a defendant to the claims of the workmen and since the workmen themselves are not interested to prosecute their case, and they do not have any industrial dispute. By the continued default of the workmen I am inclined to think that they are not interested to prosecute their case presumably because they do not have any industrial dispute subsisting at the present moment. As already stated the employers do not have any industrial dispute any more. In the circumstances I have no other option but to dispose of the case on a non-dispute award.

In the circumstances, I make a 'no-dispute' award in this case.

2nd March, 1976

K. K. SARKAR, Presiding Officer

[No. L. 29011/35/74RIV/DIV(B)]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1976

का० आ० 1123.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री मदन लाल सुपुत्र श्री चित्तर-लाल, निवास एवं डाक घर लम्बाखो, जिला बूंदी की लम्बाखो सैण्डस्टोन माईन के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

157 GI/75—4

अनुसूची

क्या श्री मदन लाल सुपुत्र श्री चित्तर लाल, खान मालिक, निवास एवं डाकघर लम्बाखो, जिला बूंदी की बूंदी जिला (राजस्थान) में लम्बाखो सैण्डस्टोन माइन्स में नियोजित श्रमिक, किन्हीं सवेतन राष्ट्रीय और त्यौहार की छुट्टियों की स्वीकृति के हकदार है ? यदि हां, तो किन छुट्टियों के और किस वर्ष से ?

[संख्या-एल-29011/134/75-डी-3/बी]

ORDER

New Delhi, the 8th January, 1976

S.O. 1123.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists beeween the employers in relation to the management of Lambhakho Sand Stone Mine of Shri Madan Lal, son of Shri Chittarlal, Resident and Post Lambhakho, District Bundi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Lambhakho Sand Stone Mines in the District of Bundi (Rajasthan) of Shri Madan Lal son of Shri Chittar Lal, Mine owner, Resident and Post Lambhakho, District Bundi, are entitled for grant of any paid national and festival holidays? If so, on what holidays and from which year?

[File No. L-29011/134/75-D-IIIB]

आदेश

का० आ० 1124.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में गौरीपुर इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, सालसबरी हाऊस, 3/1, बैंकशैल स्ट्रीट, कलकत्ता की छेन्दापथर बुल्कैम माइन् पुर्णापानी, डाकघर फुल्लकुसमा, जिला बांकुरा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या गौरीपुर इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, सालसबरी हाउस, 3/1, बैंकशैल, स्ट्रीट, कलकत्ता की पश्चिम बंगाल राज्य में छेन्दापथर बुल्फेम माइन्, डाकघर फुल्लकुसमा, जिला बांकुरा के कर्मकारों की निम्नलिखित मांगे न्यायोचित हैं । यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

मांगें

(1) अकुशल कर्मकारों को प्रति व्यक्ति 6 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का संदाय और अर्ध-कुशल और कुशल कर्मकारों की मजदूरी में तदनुरूप वृद्धि। खान के अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कर्मकारों को अनुषंगी लाभों का दिया जाना।

(2) बंदी के कारण 4-6-74 से 31-8-74 तक की बेरोजगारी की विधि के लिए कर्मकारों को मजदूरी का संदाय।

[संख्या एल-19012(44)/75-डी 3(बी)]

ORDER

S.O. 1124.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Chhendapathar Wolfram Mine Purnapani, Post Office Fulkusma, District Bankura of Gouripur Industries (Private) Limited, Salisbury House, 3/1, Bankshall Street, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the following demands of the workmen of Chhendapathar Wolfram Mine, Post Office Fulkusma, District Bankura in the State of West Bengal of Gouripur, Industries (Private) Limited, Salisbury House, 3/1, Bankshall Street, Calcutta are justified? If so, to what relief are the workmen entitled?

DEMANDS

(i) Payment of wages to the unskilled workmen at the rate of Rs. 6/- per day per head and corresponding increase in the wages of the semi-skilled and skilled workmen. Payment of other fringe benefits to unskilled, semi-skilled and skilled workmen of the mine.

(ii) Payment of wages to the workmen for the period of unemployment from 4-6-74 to 31-8-74 due to closure.

[No. L-19012(44)/75-D-III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

का० आ० 1125—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की ओरिएण्ट कोलियरी, डाकघर ब्रजराजनगर, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी डा० बी० एन० मिश्रा होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, की ओरिएण्ट कोलियरी, डाकघर ब्रजराजनगर, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा के प्रबन्धतंत्र की, श्री जी० एम० घोष, पर्यवेक्षक को, 1-1-1975 से 26-4-75 तक निलम्बित करने और अपने पत्र संख्या सी एम० ए/एल ई वी/पर/21/180, तारीख 28-4-75 द्वारा उन्हें कड़ी चेतावनी देने की कार्रवाई वैध और न्यायोचित थी यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-19012/35/75-डी 3 (बी)]

एस० एच० एस० अय्यर,
अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 27th January, 1976

S.O. 1125.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Orient Colliery of Coal Mines Authority Limited, Post Office Brajrajnagar, District Sambalpur, Orissa, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Dr. B. N. Misra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Orient Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited Post Office Brajrajnagar, District Sambalpur, Orissa, is suspending Shri G. M. Ghosh, Overman from 1-1-1975 to 26-4-1975 and administering him a severe warning vide their letter No. CMA/LEV/per/21/180 dated 28-4-75 was legal and justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-19012/35/75-D-III(B)]

New Delhi, the 6th March, 1976

S.O. 1126.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Stone Quarries of M/s. P. C. Ganguli and sons and others and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st March, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No 12 of 1975

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

ORDERS OF REFERENCE

(Ministry's order No. L-29011/61/74-LRIV. dated 27-1-75)

PARTIES :

Employers in relation to the Stone Quarries of the employers mentioned in Schedule I hereto annexed

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—None.

On behalf of the workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Stone Quarry

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the stone quarries of the employers mentioned in Schedule I annexed and their workmen in respect of the matters specified in Schedule II annexed, referred the said dispute for adjudication to this Tribunal.

SCHEDULE I

1. M/s. P. C. Ganguli & Sons, Quarry owners Mazurkola, Pakur, S.P.
2. M/s. Pakur Quarries (P) Ltd., Quarry owners, Baghajuli, Pakur, S. P.
3. M/s. Nait Ram Sagarmal, Quarry owners, Malpahari, Pakur, S. P.
4. M/s. Dayal Stone Works, Quarry owners, Khaprozolla, Pakur, S. P.
5. M/s. Otandas & Co. Quarry owners, Khaprajolla, Pakur, S. P.
6. M/s. All India Stone Co., Quarry owners, Mazurkola, Pakur, S. P.
7. M/s. Jialdass & Co., Quarry owners, Malpahari, Pakur, S. P.
8. M/s. Hindusthan Granite Stone Works, Quarry owners, Baghajulli, Pakur, S. P.
9. M/s. Gobind Ram & Co., Quarry owners, Jalpahari, Pakur, S.P.
10. M/s. Khajan Singh & Sons, Quarry owners, Bagajuli, Pakur, S. P.
11. M/s. Chhabria Engineering Works, Quarry owners, Khaprajolla, Pakur, S. P.
12. M/s. Mariwlla Stone Works, Quarry owners, Mazurkola, Pakur, S. P.
13. M/s. B. N. Saha & Co. (P) Ltd., Quarry owners, Majurkola, Pakur, S. P.
14. M/s. Mahabir Stone Supply Co., Quarry owners, Barmasia, Pakur, S. P.
15. M/s. The Secretary, Quarry Owners Association, Pakur, S. P.

SCHEDULE II

Whether the workmen of various categories of the quarries of the employers mentioned in Schedule I are entitled to the revision and enhancement of their rates of wages? If so, to what extent and from what date?"

On receipt of the reference notices were issued to all the parties. Written statements by the employers and rejoinders of the parties weer filed. The case proceeded along its course. It appears that from the month of July, 1975 the workmen or their authorised representatives ceased to appear before this Court and failed to take any steps. In July 1975 the workmen or their authorised representatives failed to appear and took no steps. Similarly the case was fixed in August, 1975, September 1975, October, 1975, November 1975, December, 1975 and January, 1976. In none of the above occasions the workmen or their authorised reprcsentatives either appeared or took any steps. Ultimately I fixeed the case for evidence and argument on 3-2-76. None of the parties or their authorised representatives appeared nor took any steps on 3-2-76. I gave another chance to them and again fixed the case for evidence and argument on 16-2-76 and recorded an order that in default of the parties to appear the case will be disposed of according to law. Then on 16-2-72 the case was called out but none of the parties appeared or took any steps. So the fact remains that since July 1975, the workmen defaulted to appear and took any steps. The fact also remains that from January, 1976, the employers also defaulted to appear and took any steps. In other words, both the employers and the workmen lost interest in the case. The case is more than one year's old the reference having been made on 27th January, 1975 Whatever may be the reason for their non-appearance, the case cannot be allowed to be kept pending indefinitely. There was no indication before me that the parties are appearing. The only inference I can draw is that the industrial dispute referred to me has ceased to exist and the parties are not interested to prosecute their respective cases. Without evidence no documents can be legally brought on record and award ceased. In the circumstances I have no other option but to pass a no-dispute award in this case.

In the result, I make a no-dispute award in this case.

21st Feb. 1976.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

[No. L. 29011/61/74-LRIV/DIIIB]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1976

का० आ० 1127.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली की जनपथ शाखा के प्रबन्धतंत्र की निम्नलिखित कर्मकारों को 13 जून, 1975 दिन के एक भाग के लिए हड़ताल पर मानने और मजदूरियों में कटौतियां करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

लिपिक :

1. श्री के० एल० गुप्ता
2. श्री आर० एल० वाधवन,
3. श्री आर० एस० शर्मा
4. श्री ए० बी० पाण्डे
5. श्री आसानन्द नागपाल,
6. श्री एस० सी० गुप्ता
7. श्रीमती ऊषा कपूर
8. श्री एम० एल० कपूर
9. श्री डी० डी० पुरी
10. श्री एच० के० नारंग
11. श्री डी० के० अहलुवालिया
12. श्री एन० के० जैन
13. कुमारी वीना जैन
14. श्री आर० के० सेठी
15. श्री एस० के० डिगरा
16. श्री आर० पी० गर्ग

17. श्री रमेश लाल
18. श्री आर० एन० मित्रा
19. श्री पी० सी० जैन
20. श्री ए० के ० कपूर
21. श्री जी० सी० गुप्ता
22. श्री परगट सिंह
23. श्री वी० के० अमर
24. श्री बी० एन० निगम
25. श्रीमती राज कुमारी
26. श्री आर० दीपचन्दानी
27. श्री वी० के० भाटिया
28. श्री एस० एस० जयरथ
29. श्री वी० के० गोस्वामी
30. श्री डी० के० मोंगा
31. श्रीमती हरिन्द्र कोहली
32. श्री जे० के० चोपड़ा,
33. श्री के० आर० बजाज
34. श्री आर० पी० बंसल
35. श्री अरुण दावे
36. कुमारी सुशीला खट्टड़
37. श्रीमती रजनी खन्ना
38. श्री एस० के० बर्मन
39. श्रीमती गंगा मलिक
40. श्री के० के० आनन्द
41. श्री जी० एस० नेगी
42. कुमारी प्रभा चौधरी
43. श्री सी० एम० पुरी
44. श्री ए० के कल्याणी
45. श्री एन० के० खन्ना
46. श्री बी० एन० सेठ
47. श्री एम० एल० वशिष्ठ
48. श्रीमती आशा शर्मा
49. श्री एम० एल० जैन
50. कुमारी बिमला लाला
51. श्री गोपाल देवानी
52. श्रीमती पी० प्रभावली
53. श्री एच० एम० श्रीवास्तव
54. श्री मोहन सिंह
55. श्री बी० डी० बंसल
56. श्री एन० के० श्रीवास्तव
57. श्री सी० डी० चावला

उप-कर्मचारी :

1. श्री बी० डी० तिवारी
2. श्री हरीश चन्द्र
3. श्री चन्द्र शेखर
4. श्री फूलचन्द
5. श्री रणवीर सिंह
6. श्री बैजनाथ कपूर
7. श्री मोहन चन्द्र
8. श्री साहीराम
9. श्री जगतनारायण
10. श्री मोहन लाल
11. श्री श्यामनारायण

[सं० एल-12011/21/75-डी-2ए]

ORDER

New Delhi, the 14th January, 1976

S.O. 1127.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Janpath Branch of the Central Bank of India, New Delhi in treating the following workmen as on strike for a part of the day on the 13th June, 1975 and making deductions in wages is justified ? if not, to what relief are the said workmen entitled?

Clerks :

1. Shri K.L. Gupta
2. Shri R.L. Wadhawan
3. Shri R.S. Sharma
4. Shri A.B. Pandey
5. Shri Asa Nand Nagpal
6. Shri S.C. Gupta
7. Shrimati Usa Kapoor
8. Shri M.L. Kapoor
9. Shri D.D. Puri
10. Shri H.K. Narang
11. Shri D.K. Ahluwalia
12. Shri N.K. Jain
13. Miss Veena Jain
14. Shri R.K. Sethi
15. Shri S.K. Dhingra
16. Shri R.P. Garg
17. Shri Ramesh Lal
18. Shri R.N. Mitra
19. Shri P.C. Jain
20. Shri A.K. Kapoor
21. Shri G.C. Gupta
22. Shri Pargat Singh
23. Shri V.K. Amar
24. Shri B.N. Nigam
25. Shrimati Raj Kumari
26. Shri R. Deepchandani
27. Shri V.K. Bhatia
28. Shri S.S. Jairath
29. Shri V.K. Goswami
30. Shri D.K. Monga
31. Shrimati Harinder Kohli
32. Shri J.K. Chopra
33. Shri K.R. Bajaj
34. Shri R.P. Bansal
35. Shri Arun Dave
36. Miss Sushila Khattar
37. Shrimati Rajni Khanna
38. Shri S.K. Burman
39. Shrimati Ganga Malik
40. Shri K.K. Anand
41. Shri G.S. Nogi
42. Miss Prabha Choudhry
43. Shri C.M. Puri

44. Shri A.K. Kalyani
45. Shri N.K. Khanna
46. Shri B.N. Seth
47. Shri M.L. Vashisht
48. Shrimati Asha Sharma
49. Shri M.L. Jain
50. Miss Bimla Lala
51. Shri Gopal Dewani
52. Mrs. P. Prabhavati
53. Mr. H.M. Srivastava
54. Mr. Mohan Singh,
55. Mr. B.D. Bansal
56. Mr. N.K. Srivastava
57. Mr. C.D. Chawla

Sub Staff

1. Shri B.D. Tewari
2. Shri Harish Chander
3. Shri Chander Shekhar
4. Shri Phool Chand
5. Shri Ranvir Singh
6. Shri Baij Nath Kapoor
7. Shri Mohan Chander
8. Shri Sahi Ram
9. Shri Jagat Narain
10. Shri Mohan Lal
11. Shri Shyam Narain

[No. L-12011/21/75-D. IIA]

आदेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1976

का० आ० 1128.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

पंजाब नेशनल बैंक और अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी फेडरेशन के बीच दिनांक 16 जून, 1973 को किए गए समझौते को ध्यान में रखते हुए (i) क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र द्वारा सर्वश्री के० एल० खन्ना, बी० डी० मेहरा और जे० पी० मिश्र को मुख्य कोषाध्यक्ष 'क' से मुख्य कोषाध्यक्ष 'ग' के रूप में पदोन्नति देने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(ii) क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र द्वारा रोकड़ अधिकारी श्रेणी 'घ' के पद की परीक्षा/साक्ष्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित मुख्य कोषाध्यक्ष 'ग' से भिन्न व्यक्तियों को अनुमति देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो मुख्य कोषाध्यक्ष 'ग' किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-12012/156/75-डी० II-ए]

ORDER

New Delhi, the 20th January, 1976

S.O. 1128.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Taking into account the settlement dated the 16th June, 1973 entered into between the Punjab National Bank and the All India Punjab National Bank Employees Federation—

(i) Whether the management of Punjab National Bank is justified in denying promotion as Head Cashier 'C' from Head Cashier 'A' to Sarva Shri K. L. Khanna, B. D. Mehra and J. P. Mishra? If not, to what relief the said workmen are entitled?

(ii) Whether the management of Punjab National Bank is justified in allowing other than Head Cashier 'C' with at least 5 years experience to appear in the test/interview to the post of Cash Officers Grade 'D'? If not, to what relief the Head Cashiers 'C' are entitled?

[No. L-12012/156/75/D. IIA]

आदेश

का० आ० 1129.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में इंडियन ओवरसीज बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालामाप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या इंडियन ओवरसीज बैंक, मद्रास के प्रबन्धतंत्र की, उस स्टाफ को जिन्हें उनके अनुरोध पर उक्त बैंक की देहरादून शाखा में स्थानांतरित किया गया था "स्पलिट ड्यूटी" भत्ता न देने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल-12011/31/75-डी II ए]

ORDER

S.O. 1129.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relaton to the Indian Overseas Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palamappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Indian Overseas Bank, Madras, in denying the payment of split duty allowance to these staff transferred to Dehra Dun Branch of the said Bank at their own requests justified ? If not to what relief are the concerned workmen entitled?

[No L-12011/31/75-D. IIA]

आदेश

का० आ० 1130.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र की, आदेश संख्या ई एस टी/363/3/75, तारीख 5 मई, 1975, जिसके द्वारा श्री गजाधर मिस्त्री, लिपिक को एक वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट सहायक के रूप में प्रोन्नति से वंचित किया गया था, जारी करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-12012/153/75-डी 2 ए]

ORDER

S.O. 1130.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Punjab National Bank is justified in issuing their order No. Est/363/3/75 dated 5th May, 1975 by which Shri Gajadhar Mistry, Clerk, was debarred from promotion as Special Assistant for a period of one year? If not to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/153/75-D.IIA]

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1976

का० आ० 1131.—यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), बम्बई के समक्ष लम्बित है ;

और, यतः, पीड़ित श्रमिक मामले को इस कारण अहमदाबाद अंतरित करने के लिए अनुरोध करता है कि वह उस स्थान का निवासी है और यह कि यदि मामले की सुनवाई बम्बई में होगी तो उसे धन-संबंधी हानि तथा असुविधा होगी ;

और यतः, मामले का बम्बई से अहमदाबाद में अंतरण प्रबन्धकों को स्वीकार्य नहीं है और उनकी आपत्ति को वाकायदा ध्यान में रखा गया है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार यह वांछनीय समझती है कि श्रमिक की सुविधा के लिए उक्त मामले की सुनवाई अहमदाबाद में होनी चाहिए और उक्त विवाद को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 1), बम्बई के समक्ष उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद को, जो एतद्द्वारा उक्त कार्यवाही के निपटान के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित किया जाता है और जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० यू० शाह होंगे, अन्तरित करती है और यह निर्देश करती है कि उक्त अधिकरण और आगे कार्यवाहियां उस प्रक्रम से करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की जाएं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा ।

अनुसूची

क्रमांक	अधिसूचना की संख्या और तारीख	पक्षकारों के नाम
1.	संख्या एल-12012/127/75/डी-2/ए, तारीख 30 अक्तूबर, 1975	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और उनका कर्मकार

[संख्या एल-12012/127/75-डी-2/ए]

ORDER

New Delhi, the 28th January, 1976

S.O. 1131.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Industrial Tribunal (No. 1), Bombay.

And, whereas, the aggrieved worker requests for the transfer of the case to the Tribunal at Ahmedabad for the reason that he is a resident of that place and he would be put for monetary loss and inconvenience if the case is heard at Bombay;

And whereas, the management are not agreeable to the transfer of the case from Bombay to Ahmedabad and their objection duly taken into account;

And whereas, the Central Government considers it desirable that the case would be heard at Ahmedabad to suit the convenience of the worker and the said dispute should be disposed of early;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute before the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1), Bombay and transfers the same to the Industrial Tribunal at Ahmedabad hereby constituted under Section 7A of said Act with Shri M. U. Shah as the Presiding Officer for the disposal of the said proceeding and directs that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Serial No.	Notification No. and Date	Name of the Parties
1.	No.L.12012/127/75/DII/A, dated the 30th October, 1975.	The United Bank of India and their workmen.

[No. L. 12012/127/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

का० आ० 1132.—केन्द्रीय सरकार की राय कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक, अम्बाला की, श्री आर एन० दास, लिपिक को सेवा-निवृत्ति का पत्र तामील कराने के बाद, उन्हें 9 अक्तूबर, 1975 से सेवोन्मुक्त करने की कार्रवाई वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-12012/167/75/डी 2ए]

आर० कुंजिथापदम अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O.1132.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constitued under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the State Bank of India Ambala in discharging Shri R. N. Das, clerk from service with effect from the 9th October 1975, after the service of the letter of retirement on him is legal and justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12012/167/75/DII/A]

New Delhi, the 28th February, 1976

S.O. 1133.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the United Commercial Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th February, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER INDUSTRIAL TRIBUNAL (III) U.P. AT KANPUR

Adj. Case No. 5 of 1975 (Central)

In the matter of an industrial dispute between the bank known as United Commercial Bank, Central Zone 23, Vidhan Sabha Marg, Lucknow.

Versus

Their workman through the Secretary, U.P. Bank Employees Association, Ashok Bhawan, Kutubkhana, Subzimandi, Bareilly.

APPEARANCES :

For the employers—Shri N. K. Tripathi, Manager of the Bank.

For the workman—Shri Gauri Shanker Gupta, State Executive Member, U.P. Bank Employees Association.

INDUSTRY :Banking. DISTRICT : Lucknow.

AWARD

By notification No. L-12012/119/74-LR-III/DIIA dated 9-7-1975 Government of India Ministry of Labour referred the following matter of dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947):

"Whether the action of the management of the United Commerical Bank in extending the probationary period and terminating the services of Shri Prahlad Prakash of their Gadarpur branch, District Nanital, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

Summons were issued to both the parties and were duly served on them. Parties filed their written statement and rejoinders. When the case was taken up for hearing on 22-1-76 an application was received on behalf of the workman concerned that he is not interested in prosecuting the case any more. The burden being on the workman, he has failed to discharge it.

It is, therefore, awarded that the workman concerned is not entitled to any relief.

Cost easy.

K. N. SRIVASTAVA, Presiding Officer,

[No. L 12012/119/74/LRIII/DII(A)]

18th Feb. 1976

New Delhi, the 8th March, 1976

S.O. 1134.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the United Commercial Bank, and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th March, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Reference No. 30 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the United Commercial Bank,

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Shri Arun Roy, with Shri G. C. Sen.

On behalf of Workmen—Shri D. P. Roy.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking.

(AWARD)

By order No. L-12012/5/75/DII/A dated 14th April, 1975, the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the United Commercial Bank and their workmen to this tribunal for adjudication. The reference reads:

"(1) Whether Mrs. Sarala Bhadalia has been performing the duties of higher responsibilty to attract special allowance in terms of paras 5-6 of the Bipartite Settlement dated the 19th October, 1966, from the 31st May, 1968 ? If so, to what relief is she entitled ?

(2) Taking into consideration the nature of duties performed by her from the 31st May, 1968 onwards, whether Mrs. Bhadalia should be designated and confirmed as Officer-in-Charge, Safe Deposit Vault? If so, with what details ?"

2. The employee in this case is one Mrs. Sarala Bhadalia who will hereinafter be referred to as Mrs. Bhadalia. She joined the United Commercial Bank on 19th June, 1965 at its main office at 10 Brabourne Road, Calcutta. She was put under training for a period of three months on joining service under Smt. Kamala Bose who was examined as WW5. WW5 was an officer in Grade D at that time. She was also in sole charge of the Safe Deposit Vault in the main office. After the training Mrs. Bhadalia continued to work in the department in the same section until she was transferred to Lala Lajpat Rai Road (Elgin Road) branch of the Bank. Since 25th May, 1968 she has been working in the branch at the Safe Deposit vault section. But there was some difficulty for Mrs. Bhadalia to go to Elgin Road branch as she was living for away from the town. Ext. W-1 dated 24th May, 1968 contains the allegation which she made against her transfer to Elgin Road branch. But in spite of those allegations she had been transferred to that branch. Ext. W1(a) is the transfer order with direction to Mrs. Bhadalia to resume duty at Elgin Road branch on 25th May, 1968. The case of Mrs Bhadalia is that she had been promised compensation by the management at the time of her transfer in view of the difficulties she expressed for the transfer. Any way, in her first letter, Ext. W-2 dated 25-3-71, she claimed special allowance for the work she had been doing in the Safe Deposit locker section since 31st May, 1968. Ext. W-2 had been received by the management on 29-3-1971. Ext. W2(a) is the copy of the letter which they received. Again on 6th May, 1971 Mrs. Bhadalia made another application vide Ext. W-3 asking for special allowances to be paid to her. Ext. W-4 dated 15th July, 1972 is a similar letter which was followed by Ext. W-5 letter dated 4-7-1974 giving the details of her work at the office at Safe Deposit Vault Section. But in spite of these applications the management did not take any step in the mater. Mrs. Bhadalia, therefore, approached the United Commercial Bank Employees Union, West Bengal of which she is a member to take up her cause as a result of which the Union passed Ext. W-6 resolution taking up the cause of Mrs. Bhadalia to the management and also directing its parent body, All India United Commercial Bank Staff Federation to which the Union was affiliated to take up the matter at all the appropriate levels on behalf of Mrs. Bhadalia. As a result of the attempt of the union there was a conciliation proceeding at the instance of the Assistant Labour Commissioner, Central. But that attempt proved a failure. Ext. C-1 is the failure report attached with the connected papers in the proceedings. Ext. C-2 is the Constitution of the All India United Bank Staff Federation.

3. The Union on behalf of Mrs. Bhadalia contended that on the basis of general rules for payment of special allowance in the Bipartite settlement dated 19th October, 1966 she is entitled to get special allowance for the work she had been doing at the Safe Deposit Vault involving greater skill or responsibility. It is also stated in the written statement filed by the union that Mrs. Bhadalia has been doing work of an officer being in sole charge of Safe Deposit Vault and as such she must be paid her allowance as an officer in charge of the Safe Deposit Vault.

4. On behalf of the United Commercial Bank a written statement has been filed denying all the allegations by the union in their written statement. They state that Mrs. Bhadalia is not entitled to the special allowance as according to them she is doing the work of a clerk and that her work was being checked and supervised by higher authorities from time to time. They also stated that there is no skill or responsibility required in attending the work at the Safe Deposit Vault which she has been doing. The work they stated is that of an ordinary clerk. In addition to this allegation it is also stated in the written statement that there has been no industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act between the Bank and Mrs. Bhadalia and the All India United Commercial Bank Staff Federation or its General Secretary have no locus standi to raise an industrial dispute on behalf of Mrs. Bhadalia or to espouse her cause or represent here before the Tribunal.

5. Out of the above contentions the following issues arise for consideration:

(i) Whether the claim of Mrs. Bhadalia has been properly espoused by the Union of which she is a member.

(ii) Whether the claim for special allowance on the basis that Mrs. Bhadalia has been functioning in a post which involves greater skill or responsibility within the general rules as well as Appendix B regarding special allowance duties as provided for in the Bipartite Settlement dated 19th October, 1966 is sustainable ?

6. Issue No. (i) :

It has to be stated at the outset that the Bank did not make any allegation in the written statement that the concerned union had not espoused the cause of Mrs. Bhadalia either by a resolution or by any other conduct and as such no industrial dispute had come into existence, though they stated in paragraph 1 of the written statement that there was no industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act. An averment in paragraph 3 of the written statement does not specifically advert to any dispute with regard to the sponsoring of the case of Mrs. Bhadalia by the concerned union. It is well established that want of a specific plea in the written statement would be fatal to the contention on a question of fact (see Manager of Messrs K. J. Khosla & Co. Pvt. V. Vedrai Bhalla and Ors., 1976) Labour Industrial Cases, 1475 (Delhi High Court). Any way, having heard the argument I will answer the contention raised by the Bank.

7. It is well established that in every case it is necessary to ascertain whether an individual dispute has acquired the character of an industrial dispute, the test being whether at the time of reference the dispute was taken up and supported by the union of the workmen of the employer against whom the dispute is raised by individual workman or by an appreciable number of workmen. Put it in another way, in order that an individual dispute may become an industrial

dispute it has to be established that it had been taken up by the union of the employees of the establishment or by an appreciable number of employees of the establishment.

8. It is the case of the United Commercial Bank Employees Union that Mrs. Bhadalia is a member of that union. That fact could not be disputed as the union has produced their register showing her membership of the union. Name of Mrs. Bhadalia finds a place in that register. It is also established that the United Commercial Bank Employees Union which is a registered union has been affiliated to All India United Commercial Bank Staff Federation. WW2 is the present General Secretary of the United Commercial Bank Employees Union as well as the Joint Secretary of the All India United Commercial Bank Staff Federation. WW4 is the General Secretary of All India Allahabad Bank Employees Association. Sri D. P. Roy who conducted the case on behalf of Mrs. Bhadalia is admittedly the General Secretary of All India United Commercial Bank Staff Federation. The evidence of WW2 is that the Executive Committee of the United Commercial Bank Employees Union passed a resolution, a copy of which is marked Ext. W-6, to the effect that the request of Mrs. Bhadalia who was the member of the union and which was passed unanimously to take up her case for payment of due allowance as well as to confirm her as an officer in the Safe Deposit Locker in the Elgin Road branch of the United Commercial Bank. The second part of that resolution was that the matter be referred to the All India United Commercial Bank Staff Federation to which the union is affiliated with a request to take up the matter at all levels. The resolution was passed on 21-12-1968 at 2, India Exchange Place which is the office of the Union. The copy was compared with the original in the Minutes Book produced before the Tribunal. The original was read over in Court and it is found to be correct. It was signed by 12 members of the Executive Committee. WW2 was one of the signatories. This resolution is sufficient to hold that the union had taken up the cause of Mrs. Bhadalia. But it is contended on behalf of the Bank that no such resolution had been passed by the All India United Commercial Bank Staff Federation and as such the espousal of the cause of Mrs. Bhadalia as evidenced by Ext. W6 cannot be sustained. WW2 stated that a similar resolution had been passed by the parent Union.. It is clear from the evidence that after passing of the resolution the parent Union had taken up the cause of Mrs. Bhadalia. They appeared before the Conciliation Officer who prepared Ext. C-1, the failure report. They filed the written statement on behalf of Mrs. Bhadalia. The fact that the United Commercial Bank Employees Union is affiliated to the All India United Commercial Bank Staff Federation is sufficient to establish that the espousal by the unit is tantamount to the espousal of the cause by the parent body itself. It is well settled that in order that a dispute between a single employee and its employer could be validly referred to under Section 10 of the Act, it is necessary that it should have been taken up by the union to which the employee belongs or by a number of employees. On this view the dispute between an employee and the employer cannot by itself be treated as an industrial dispute unless it is sponsored or espoused by a union or a number of workmen. That line of approach has been accepted in the case of Workers of Dharampal Premchand V Dharampal Premchand, 1965 I LLJ. 668. In this case the Supreme Court was dealing with the matter whether there was a resolution by the Working Committee as in this case. In that case also the workmen relied upon the minutes of a meeting. The union in this case maintains that the resolution was sufficient proof of espousal of the dispute by the unit of a parent body. That the Executive Committee of a union has got such power to espouse the dispute has been held in Mysore High Court in a decision between Krishnarajendra Mill v Assistant Labour Commissioner 1968 I LLJ 514. In view of the law as laid down above and as much as there is clear evidence in this case that there was a resolution of the Executive Committee to espouse the cause of Mrs. Bhadalia passed by the Executive Committee on 21-12-1968 and signed by 12 members of the Committee. I have no doubt that in this case there is an industrial dispute and this is not an individual dispute. So, this issue is found against the management.

9. There is yet another question raised by the management with regard to the signing of the written statement by the Secretary of the Union. It is contended on behalf of the management that the written statement should have been signed by Mrs. Bhadalia herself. I am unable to accept this contention. Once it is found that the cause of Mrs. Bhadalia was espoused validly by the Union there is no necessity for Mrs. Bhadalia herself to sign the written statement and that it could be signed by the official of the Federation to which the United Commercial Bank Employees Union is affiliated. There is no substance in this contention.

10. Issue No. (ii):

This is important issue in the case. The evidence of Mrs. Bhadalia examined as WW1 is that she first took her training for about three months in the Safe Deposit Vault Section in the main office of the bank at Brabourne Road under Sm. Kamala Bose who was the Officer in-charge of that Section. After training she worked in the same section of the main office until May, 1968 when she was transferred to the Elgin Road branch. Her claim is for special allowance under the Bipartite Settlement as she has been functioning in a post which involves greater skill or responsibility. It is admitted that she has been working only in the Safe Deposit Section over since she was transferred to the branch. There is no assistant in her section, and she was in sole charge of the Section. When she joined the section, the branch in Elgin Road was newly established in May, 1968. So, Mrs. Bhadalia joined the branch on opening it in May, 1968. In 1968 when the branch was opened there were about 318 lockers in the section but later on it was doubled and at present there are about 1,100 lockers in the section. The customers first go to Mrs. Bhadalia. One of the keys of the locker would be kept with the customer. Mrs. Bhadalia would open the locker and it will be operated by the customer thereafter. There is a series of register maintained in the Section. Ext. M3 is the register of application for lockers. Ext. M-4 is the daily register and Ext. M5 is renewal register. In each of these registers Mrs. Bhadalia has been putting her signature either as Custodian or as Controlling Officer. It is part of her duty to verify the signature of the customer on the basis of the application they file. Ext. M-1 is the application form signed by the customers. Ext. M8 is the Key register and Ext. M-2 is the ledger. Ext. M-7 is the file in which the work is allotted to her. Ext. M-7(a) is the relevant page which contains office order by which pending work and other work were allotted to Mrs. Bhadalia on her return from leave. Similar office orders have been maintained in Ext. M-7 showing the work which has been allotted to her. That she has been doing a work involving greater skill as responsibility is well established in the light of evidence of WW5 Sm. Kamala Bose. She stated in her deposition as follows: "The locker register is signed by the Custodian (G 126 register). G 125 register is also signed by the Custodian. The Key register is signed by the custodian. G 128 main book I sign as Custodian. G-127 Renewal register is signed by the Custodian. The application form for hiring locker is signed by the Custodian and the Manager." WW5 was in sole charge of the Safe Deposit Vault in the main office of the bank, and she has been signing these registers in the capacity of a Custodian. The word custodian or controller is attached to the person who performs duty in the Safe Deposit Vault. It is in the same manner as Controller or Custodian that the work was being performed by Mrs. Bhadalia in her section in the Elgin Road branch. The evidence of WW4 who is a clerk in the Allahabad bank is to the effect that in all branches of his bank the Safe Deposit Vault was manned by special assistants. No case has been brought to my notice to establish that a clerk had opted the Safe Deposit Vault any other bank or its branches. WW3 was in the main office of the bank for a short period when Mrs. Bhadalia was working in the Safe Deposit Vault in the Calcutta main office. His evidence is not of much consequence though he has stated in his evidence that Mrs. Bhadalia made a representation to Sri Purohit who was the General Manager at the time that she should be paid her allowance and that he knew that Purohit had told her that if rules permitted she might be given some functional allowance if her function attracted the allowance. This is a circumstance to show that at some stage Mrs. Bhadalia had made representation to the management for getting special allownce. In spite of the fact that Mrs. Bhadalia had sent several representations to the management claiming for special allowance none had reached the higher authorities in the Bank. Witness no. 1 for the management is one Sri Mongal. He admitted that he never got any representation from Mrs. Bhadalia. Neither MW 1 nor WW 6 could enquire into the grievance of Mrs. Bhadalia. It is not explained as to why the applications of Mrs. Bhadalia were not sent to the higher authorities for passing orders thereon as find even as early as in

1968 Mrs. Bhadalia had put forward a claim for special allowance. WW6 was also for sometime Agent of the Elgin Road branch where Mrs. Bhadalia worked as in charge of Safe Deposit Vault. That she worked in the section being in sole charge has to be admitted. That she had also in sole supervision of the section is also borne out of the evidence.

11. Paragraphs 5.6, 5.7 and 5.8 in the general rules regarding special allowance in the Bipartite Settlement dated 19th October, 1966 provide that all workmen would be entitled to special allowance if he is required to perform duty or duties or undertake the responsibility listed against the category irrespective of his designation, nomenclature or any general authority vested in him. Appendix B in Chapter V on Special Allowance duties provided as against item (xix) that the Special assistants duties involve—(iii) Checking all vouchers, advices, statements, bills, returns, books of accounts, etc. and item (iv) provides checking current, savings and other ledgers. That there had been checking of books of accounts and that there had been checking of ledgers maintained in the bank by Mrs. Bhadalia were proved beyond dispute. It is contended that checking should be the work of superior officer in respect of the work performed by his subordinates. It is contended that Mrs. Bhadalia never checked the work of any subordinates. It is not correct to restrict the meaning of checking in that way. Mrs. Bhadalia had to check the registers and books of accounts in regard to identity of the customers in relation to their specimen signatures kept and maintained in her custody and satisfy herself that the customer appeared before her was the genuine or proper person. It is not open to Mrs. Bhadalia, in-charge of the section to open the locker and make it available to any person who comes to the office. The person who performs the duties at the section must be satisfied that the customer is a genuine customer whose signature is in consonance with the signature in his application. Mrs. Bhadalia has to check the signature of the customer in relation to their application before the customer is permitted to operate on the locker. It has already been pointed out that Mrs. Bhadalia had signed the relevant registers as Custodian as well as Controlling officer though they were in some places counter-initialled at random by the Agent. In the Daily Register and register of application and also the renewal register Mrs. Bhadalia had signed as a custodian or as a Controlling officer. No objection was raised by the Agent or the Accountant for her affixing signature in those documents. If there had been any fault in the maintenance of the register or in any document connected with it Mrs. Bhadalia would have been taken to task. She had a responsibility for the up keep and maintenance of these registers. The evidence of the witnesses examined on behalf of Mrs. Bhadalia has established that Mrs. Bhadalia had to perform some work involving skill or responsibility which she had been doing ever since 31st of May, 1968, She had been in sole charge of that section.

12. It is, however, attempted to make out a case that one Krishnan, Officer of the bank had promised a sum of Rs. 1,000/- as a lump sum to be paid to Mrs Bhadalia at some stage of his representation in lieu of her service in the section on the basis of the final settlement of the claim. Mrs. Bhadalia had stated this in her evidence and WW2 the Secretary of the Union had also corroborated that statement. But this aspect of the case has not been put forward in the written statement as such and there is also disparity in the evidence of WW1 and WW2 on this question. I am, therefore, not satisfied that Mrs. Bhadalia had established any case on the basis of an agreement to pay a lump sum in lieu of her past service in the Safe Deposit Vault section Any way, the evidence has established that she has been performing the duty involving skill or responsibility all along in her section. Her special responsibility would, therefore, entitle her to the allowance which is attached to the post of a Special Assistant though she is only a clerk in the department.

13. On an analysis of the entire evidence in the case I am constrained to hold that the claim of Mrs. Bhadalia is sustainable and as such she is entitled to special allowance attached to an office of a Special Assistant from 31st May, 1968.

14. There is another part in the reference which states whether Mrs. Bhadalia should be designated and confirmed as Officer in-charge of Safe Deposit Vault. I do not think such a claim is sustainable. Even Mrs. Bhadalia has stated in her evidence that she is satisfied with the special allowance and prayed for an award in respect of work in the Safe Deposit Vault. It is not open to this Tribunal to designate her as an Officer. In the absence of any material on record, it could not be said that her claim for confirmation as an Officer in-charge of the Safe Deposit Vault is valid. So, this part of the reference is found against Mrs. Bhadalia.

15. In the result, the first part of the reference is answered in favour of Mrs. Bhadalia to the effect that she is awarded special allowance as that of Special Assistant with effect from 31st May, 1968 onwards with all other benefits attached to it. Out of the period of the claim the amount which had already been paid to her as per annexure "D" to Ext. C-1, failure report, as well as the amount if any received by her for any period she worked in any other post involving payment of special allowance; in other respects the reference is rejected.

An award is passed as above.

25th February, 1976 E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-12012/5/75-DII(A)]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

का० आ० 1135.—मैसर्स ट्रांसओशियन शिपिंग एजेन्सी (प्राइवेट) लिमिटेड, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियजकों और उनके कर्मकारों, ने, जिनका प्रतिनिधित्व परिवहन और गोदी श्रमिक संघ, मुम्बई करता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में वर्णित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत विषयों के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करें ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या, 2, मुम्बई, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स ट्रांसओशियन एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र की श्री एल० ए० ग्रेशियस, लिपिक की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो श्री एल० ए० ग्रेशियस किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल-31013(2)/75-डी-4 (ए)]

ORDER

New Delhi, the 27th January, 1976

S.O. 1135.—Whereas the employers in relation to the management of Messrs Transocean Shipping Agency (Private) Limited, Bombay and their workmen represented by the Transport & Dock Workers' Union, Bombay have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Transocean Shipping Agency Private Limited, Bombay, in terminating the services of Shri L. A. Gracias, Clerk, is legal and justified? If not, to what relief is Shri L. A. Gracias entitled ?

[No. L-31013(2)/75-D.IV(A)]

आदेश

का०आ० 1336.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कांटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, विशाखापत्तनम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स कांटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन (प्राईवेट) लिमिटेड, ठेकेदार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के प्रबन्धतंत्र की श्री मोहम्मद फारुक, डम्पर प्रचालक को 6 दिसम्बर, 1974 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-34012/5/75-डी० 4(ए)]

ORDER

S.O. 1136.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Continental Construction (Private) Limited, Visakhapatnam and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and Clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which T. Narasing Rao shall be the Presiding Officer with headquartres at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Continental Construction (Private) Limited, Contractors, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam in dismissing Shri Mohd. Faruq, Dumper Operator, with effect from the 6th December, 1974 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-34012/5/75/D. IV(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1976

का० आ० 1137.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स मुरारी ट्रेडिंग कम्पनी की लक्ष्मी जोटे अभ्रक खान, डाकघर तिसरी, जिला गिरिडिह के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स मुरारी ट्रेडिंग कम्पनी की लक्ष्मी जोटे अभ्रक खान के प्रबंधतंत्र को, 15-3-75 को उपाबंध 1 में निर्दिष्ट 33 कर्मकारों को जबरी-छुट्टी पर भेजने और बाद में 15-4-75 को उपाबंध 2 में निर्दिष्ट 22 कर्मकारों की छंटनी करने और अन्त में 15-5-75 को खान बन्द कर देने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

उपाबंध 1

काम बंदी पर भेजे गए श्रमिकों की सूची

1. श्री डी० एस० लाल
2. श्री जी० बी० राणा
3. श्री शंकर लाल शर्मा
4. श्री एन० के० कारिवाला
5. श्री माधव चन्द्र डे
6. श्री विजोय नारायण सिंह
7. श्री कपिलदेव सिंह
8. श्री सम्भु नाथ सरकार
9. श्री शिव नन्दन पांडे
10. श्री जादु प्रसाद
11. श्री नागेश्वर सिंह
12. श्री गोकुल राम
13. श्री मथरा लोहार
14. श्री दाहु लोहार
15. श्री नन्दु प्रसाद सिंह
16. श्री राजकिशोर सिंह
17. श्री विश्वनाथ चौबे
18. श्री जगन्नाथ दिवेदी
19. श्री महावीर राणा
20. श्री भागल राय
21. श्री सोना कुमार
22. श्री सुखु हेमब्राम
23. श्री सोम्रा मुर्मु,
24. श्री भागी राय संख्या 2
25. श्री भारत गोपे
26. श्री ठाकुरी राय
27. श्री भोली कुमार
28. श्री भातू राय
29. श्री वासुदेव लोहार
30. श्री चेतन राय
31. श्री सुन्दर लोहार

32. श्री कमल राय
33. श्री सहदेव राणा

उपाबन्ध 2

उन श्रमिकों की सूची जिनकी सेवाएं 15-4-75 से समाप्त की गई थी ।

1. श्री बी० पी० सरकार, मेट
2. श्री रामपूजन भारती, दरवान
3. श्री शिवजीत सिंह, दरवान (ii)
4. श्री मंगेर, राय, दरवान (ii)
5. सुकर गोप, उत्स्फोटक
6. श्री जीतन गोप, उत्स्फोटक
7. श्री पारगान हास्दे, अकुशल
8. श्री जगदीश शाव, अकुशल
9. श्री चन्द्र हेमराम
10. श्री जानकी राय, हस्त छिद्रक
11. श्री कालेश्वर राय, विस्फोटक वाहक
12. श्री चोट्का हास्डे, अकुशल
13. श्रीदगन शाय, अकुशल
14. श्री बिष्णा सोरेन, अकुशल
15. श्री टेकन गोप, अकुशल
16. श्री गणेश राणा, अकुशल
17. श्री बिष्णा मुर्मु 2, अकुशल
18. श्री सोम्रा सोरेन, अकुशल
19. श्री भादो हास्दे, अकुशल
20. श्री नायक हास्दे, अकुशल
21. श्री चर्क हेम्ब्रोम, अकुशल
22. श्री सोम्रा हास्दे, अकुशल

[संख्या एल० 28011(1)/75-डी-4(बी)]
नन्दलाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 30th January, 1976

S. O. 1137.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Laxmijote Mica Mine of Messrs Murari Trading Company, Post Office Tisri, District Giridih and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Laxmijote Mica Mine of Messrs Murai Trading Company in laying off 33 workmen specified in Annexure I on 15-3-75 and subsequently retrenching 22 workmen specified in Annexure II on 15-4-75 and finally closing down the Mine on 15-5-75 is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?

ANNEXURE I

List of laid-off workers

1. Sri D. S. Lal
2. Sri G.B. Rana
3. Sri Shanker Lal Sharma
4. Sri N.K. Kariwala
5. Sri Madhab Chandra De.
6. Sri Bijoy Narain Singh
7. Sri Kapildeo Singh
8. Sri Sambhu Nath Sarkar
9. Sri Shiv Nandan Pandey
10. Sri Jadu Pd.
11. Sri Nageshwar Singh
12. Sri Gokul Ram
13. Sri Mathra Lohar
14. Sri Dahu Lohar
15. Sri Nandu Pd. Singh
16. Sri Rajkishore Singh
17. Sri Bishwanath Choubey
18. Sri Jagannath Divedi
19. Sri Mahabir Rana
20. Sri Bhagal Rai
21. Sri Sona Kumar
22. Sri Sukhu Hembram
23. Sri Somra Murmu
24. Sri Bhagi Rai No. 2
25. Sri Bharat Gope
26. Sri Thakuri Rai
27. Sri Bholi Kamar
28. Sri Bhatu Rai
29. Sri Basudeo Lohar
30. Sri Chetan Rai
31. Sri Sundar Lohar
32. Sri Kamul Rai
33. Sri Sahadeo Rana

ANNEXURE II

List of workers whose services were terminated from 15-4-75

1. Sri B.P. Sarkar, Mate.
2. Sri Rampujan Bharati, Darwan
3. Sri Shivajit Singh, Durwan (ii)
4. Sri Manger Rai, Durwan (ii)
5. Sri Sukar Gope, Blaster
6. Sri Jitan Gope, Blaster
7. Sri Pargan Hasde, Unskilled
8. Sri Jagdish Shaw, Unskilled
9. Sri Chander Hemrom
10. Sri Janki Rai, Hand Driller
11. Sri Kaleshwar Rai, Explosive Carrier
12. Sri Chotka Hasde, Unskilled
13. Sri Dagan Rai, Unskilled
14. Sri Bishna Soren, Unskilled
15. Sri Tekan Gope, Unskilled
16. Sri Ganesh Rana, Unskilled
17. Sri Bishna Murmu II, Unskilled
18. Sri Somra Soren, Unskilled
19. Sri Bhado Hasde, Unskilled
20. Sri Naika Hasde, Hnskilled
21. Sri Chark Hembrrom, Unskilled
22. Sri Somra Hasde, Unskilled

[No. L-28011(1)/75-D-IV(B)

New Delhi, the 28th February, 1976

S.O. 1138.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th February, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 28 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the Calcutta Port Commissioner, Calcutta,

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Shri S. M. Banerjee, Labour Adviser and Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Shri A. L. Roy, Adviser-cum-Organising Secretary and of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Port & Dock.

AWARD

By Order No. L-32012/2/75-DIV(A) dated 5th April, 1975, the Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Calcutta Port Commissioners, Calcutta and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads as :

"Whether the action of the management of the Calcutta Port Commissioners in not paying wages to Shri Patai Kurmi, Unskilled labour (TK No. 207), attached to Marine Foreman's section under Chief Mechanical Engineer's Department for the period from 31-3-72 to 5-7-73 was justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. Shri Patai Kurmi entered the service of the Calcutta Port Trust on 23-5-1945 in class IV category. A service register was maintianed in his name at the office of the Calcutta Port Trust. It is marked as Ext. M-1. The age of employee was shown as 29 years on 23-5-1945 which was the date of his entry into the service. But, later on 31-3-1948 the employee was sent to the Medical Officer of the Port Trust for medical examination. Ext. M-2 is the notice which was sent to the Medical Officer in all cases where examination of the employees was to be conducted. On the basis of that intimation the Medical Officer issued Ext. M-3 medical certificate in favour of the employee describing his age as 36 years on 31-3-1948. But the description of the age in Ext. M-3 was not in conformity with the age recorded in Ext. M-1, service register. Any way, the employee was to retire from service on 31-3-72 on attaining the age of superannuation at 60. On the basis of the age recorded in Ext. M-3, medical certificate, the Port Trust directed the employee to retire from service with effect from 31-3-1972. But, thereafter the union to which he was a member wrote to the Port Trust on 8-1-1973 that the correct age of the employee was not 36 years as shown in Ext. M-3 medical certificate but it was 29 years as recorded in Ext. M-1, service register. On verification the Port Trust was satisfied that his age was 29 years as entered in Ext. M-1, service register. Accordingly, a notice was again issued to the employee as per Ext. M-5 on 29-5-1973 directing the employee to resume duties. The employee rejoined his service on 617-1973 on the basis of Ext. M-5 notice. The employee now claims that he was entitled to be paid his full salary for the period from 31-3-1972 to 5-7-1973. The Port Trust, on the other hand, had treated the period of absence as on duty under ordinary leave rules and accordingly he was paid full pay from 31-3-72 to 3-6-72, half pay from 4-6-72 to 22-6-72 and thereafter on no pay. The question for consideration is whether the employee is entitled to the full salary for the period of his absence from 31-3-72 to 5-7-73, that is the period of claim disputed in the reference.

3. Both sides adduced no oral evidence but the statement of facts as contained in their respective written statements had been adopted and argument heard from both sides. A service book had been handed over to the workman after he was appointed to the service. That book is marked as Ext. W-1. The age recorded in that book is 29 years as on 23-5-45 which was his first entry to the service. After having recorded the age as 29 years in Ext. M-1 as well as in Ext. W-1, it was not open to the employers, i.e. the Port Trust authorities to make an alteration in the age. It so transpires that the employee was examined by a Doctor sometime on 31-3-48 and issued Ext. M-3 certificate. There is nothing in that certificate to show the grounds on which the Medical Officer fixed the age of the employee. In the circumstances of the case it could be an age only and not correct age unless it was established that the Doctor had taken into consideration the relative circumstances which led him to conclude that the age was 36 years on 31-3-48. There is no reason to think that the employee in this case made a false declaration of his age at the time of his entry into the service. As a matter of fact, the age as entered in Ext. M-1 as well as in Ext. W-1 had been found correct even by the Port Trust authorities on a subsequent consideration of the circumstances of the case and the Port Trust had made an endorsement in the first page of Ext. M-1 that the untampered record of age in the service sheet as 29 years on 23-5-45 was accepted as correct. The Labour Officer had also verified the service register on 20-11-1972 and made a record on first page of Ext. M-1 that the untampered record of age as on 23-5-45 as 29 years was correct. The Port Trust having accepted the correctness of the employee's age as on 23-5-45 at 29 years, it is not open to them to state that the employee would not be entitled to the salary for the period of his absence from duty. If the management had been a little vigilant, they should have adopted the age as recorded in Ext. M-1 and W-1 as correct and allowed the employee to continue in service even after 31-3-72. It is not part of the employee's fault that he was ousted from service. The material on record on the basis of Ext. M-3, medical certificate, is not sufficient to conclude that the age of the employee was correctly assessed in 1948. Taking into consideration all these circumstances I am constrained to hold that Shri Patai Kurmi, the employee in the case would be entitled to full salary from 31-3-1972 to 5-7-1973.

4. It is admitted that the employee had already received leave salary during the period and it is also admitted that he had withdrawn the full gratuity amount which stood in his credit on the date of his retirement on 31-3-72. So, the cash payment of the amount to be found due to the employee as his full salary for the period in question shall not be paid to him. It shall be paid only on his retirement.

5. In the result, an award is made in favour of Sri Patai Kurmi, Unskilled Labour, directing the Calcutta Port Trust to pay him the full salary for the period from 31-3-72 to 5-7-73 but the payment shall be deferred until he retires from service.

18th February, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

[No. L-32012/2/75-D. IV(A)]

S.O. 1139.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th February, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 29 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners,

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Shri S. M. Banerjee, Labour Adviser and Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Shri A. L. Roy, Adviser-cum-Organising Secretary of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Post & Dock.

By Order No. L-32012/3/75-DIV(A) dated 8th April, 1975, the Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Calcutta Port Commissioners, Calcutta and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads as :

"Whether the action of the management of Calcutta Port Commissioners in not paying wages to Shri Briz Mohan Ahir, Mason, T. K. No. PF/88, attached to Pattern and Foundry Shop under Chief Mechanical, Engineer's Department for the period from 23-12-1973 to 16-5-1974 was justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. The workman Shri Briz Mohan Ahir entered the service of the Calcutta Port Trust on 19-2-1949 as an unskilled labour and his service was regularised with effect from 29-12-1949. On his first entry to the service his date of birth was recorded as in the year 1921. Ext. W-2 is the service certificate issued to him at the time of his entry to the service and his age is shown in that service certificate as 28 years at the time. Subsequently he was sent to the Medical Officer of the Port Trust and on his examination which was said to be on 24th December, 1949 the age was found to be 34 years. Ext. M-2 is a duplicate copy of the medical certificate. On the basis of the age fixed at 34 years in Ext. M-2, entry was made in Ext. M-1, service register, to the effect that the age was 34 years as on 24-12-1949. Thereafter the employee was promoted to Class III with effect from 3-11-58. On the basis of his age recorded in Ext. M-2, medical certificate he was to retire on 24-12-1973 on the attainment of 58 years fixed for superannuation in the case of class III employees. On 7-11-1973 he was directed to retire from service with effect from 24-12-1973. Ext. M-4 is the notice issued to him. While he was in service he had sent a letter dated 29-11-1973 to the Port Trust disputing the correctness of his age as entered in his service register, Ext. M-1. On the basis of that application the Port Trust made the scrutiny of their records and they found that the age as set-forth in Ext. W-2, service certificate issued to employee was correct. So, the Port Trust accepted his age as 28 years on 19-2-1949 which was the date of his first entry to the service. By this time the workman had retired with effect from 24-12-1973. But he was restored to service on 17-5-1974. On his re-entry to the service the Port Trust offered him full pay from 24-12-1973 to 22-4-74 and half pay from 23-4-74 to 16-5-74 which was the period of his absence from duty and was treated as on leave. The workman did not accept the leave salary and on the other hand, contended that he was entitled to full salary for the period from 24-12-73 to 16-5-1974 which is the period of dispute under reference.

3. In this case both sides produced some documents which were marked as Exhibits with consent but no oral evidence was adduced by them. The statement of facts as stated in their respective written statements was adopted and argument heard of both the parties.

4. In this case the Port Trust had accepted the employee's age as correct on the basis of the entry made in Ext. W-2, the service certificate which was issued to the employee on his entry into the service on 19-2-1949. The date of birth as shown in Ext. W-2 as in the year 1921 and the age of the employee was shown as 28 years in the document. The medical certificate evidenced by Ext. M-2, however, mentioned the age as 34 years. The original of Ext. M-2 is not before the Tribunal. Evidently Ext. M-2 is a copy of the original. It is not explained as to how the original seal showing the date of medical examination could be affixed to Ext. M-2. The original seal could not have been affixed to Ext. M-2. The entry of the registered number as well as the date of medical examination written within the circle of the rubber-seal in the exhibit appears to have been done for the purpose of the enquiry. In the absence of any explanation the authenticity of Ext. M-2 cannot be vouchsafed. Any way, there is no material before the Tribunal to hold that the age shown as 34 years in Ext. M-2 was arrived at on a consideration of all the relevant facts in fixing the age of the employee. In the absence of any such material the age recorded in Ext. M-2 cannot be accepted. On the other hand, we have to accept the age which was recorded in Ext. W-2 as 28 years as on 19-2-1949. The Port Trust had also accepted that age as correct. The workman is not bound by the entries made in Ext. M-3 service register as it was seemed to have been prepared after the controversy had arisen. Ext. M-3 by itself cannot be accepted as an admission on the part of the employee for the correctness of his age. At the time Ext. M-3 was prepared the Port Trust had in custody the correct age of the employee as shown in Ext. W-2. The Port Trust having accepted the age as entered in Ext. W-2 as correct, it is not open to them to hold that the employee would not be entitled to his full salary for the disputed period. It was not his fault that the age was suppressed. If the management had been vigilant then it would have seen that the age was 28 years when the employee entered the service on 19-2-1949. The Port Trust has accepted that age as correct. In these circumstances the Port Trust should pay the full salary due to the workman from 23-12-1973 to 16-5-1974. I find that the workman is entitled to his full salary during the period.

5. In the result, an award is passed in favour of the employee Shri Briz Mohan Ahir, Mason, directing the Port Trust to pay to him the full salary to which he would be entitled for the period from 23-12-1973 to 16-5-1974.

Dated, Calcutta,

18th February, 1976.

[No. L-32012/3/75-D-IV(A)]

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

S.O. 1140.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th February, 1976.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS.

(Constituted by the Central Government)

Industrial Dispute No. 86 of 1975

In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited, Madras).

BETWEEN

The workmen represented by—

The General Secretary,

Madras Port and Dock Workers Congress,

No. 11, Phillips Streets, Madras-1.

AND

The General Manager,

Minerals & Metals Trading Corporation of India Limited, No. 6, Esplanade, Madras-1.

Reference :

Order No. L-33011/2/75-D. IV(A), dated 6th December, 1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final disposal in the presence of Thiru P. T. Ramalingam, Manager of the Union and of Thiruvalargal M. Naganathan, Joint Manager and Y. S. B. Sastry, Assistant Divisional Manager of the Company for the Management, upon pursuing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and the parties having filed a memorandum of settlement and recording the same, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India have in their order No. L-33011/2/75-D. IV(A), dated 6th December, 1975, referred a dispute between the employers in relation to the management of Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited, Madras and their workmen in respect of the matter specified below :—

"Whether the demand for the payment of night shift allowance from the 1st January, 1974 to the Tally Supervisors and Muzdoors engaged directly by the Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited, Madras is justified ? If so, to what relief are the workmen entitled ?"

2. The parties were served with summons.

3. A claim statement was filed on behalf of the workmen on 5-1-1976 settling out all their claims.

4. The management filed a counter statement on 17-1-1976 disputing their liability.

5. On 6-2-1976, a settlement was filed by the parties and then the case was adjourned to 7-2-1976 for appearance of the signatories for recording of the same.

6. Today, when the dispute was called the signatories to the settlement were present and they admitted the settlement.

7. I have gone through the settlement. I find that the settlement is fair and equitable. Hence the settlement is recorded.

8. An award is passed in terms of the settlement. The settlement shall form part of the award. No. costs.

7th February, 1976.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

Industrial Dispute No. 86 of 1975

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER RULE 58 OF THE INDUSTRIAL DISPUTES (CENTRAL) RULES 1957 SIGNED ON 5-2-1976

BETWEEN

The General Secretary
Madras Port & Dock Workers' Congress,
11, Philips Street, Madras-1.

AND

The Management,
Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited, 6, Esplanade, Madras-1.

Short Recital of the case

1. The Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited is a Government of India Undertaking and carries on business of exporting Iron ore among other things. It employs 44 Mazdoors and 7 Tally Supervisors in Madras Harbour mainly to pick up foreign materials from the ore unloaded in the plots in the area known as Mechanical Ore Loading Plot and south of MOLP and to do this track clearance work. Apart from this, the Corporation has engaged two handling agents, M/s. C. K. Balasubramaniam for JD-IV and VI plots till 31-12-1975 and M/s. Western Agencies for JD-II plots for the purpose of receiving ore brought within the port premises by the railway wagons by the Corporation, unloading the same from the wagons, weeding out the foreign materials from the ore etc. For that purpose they have engaged therein Tally Supervisors and Mazdoors for doing the track clearance and picking up foreign materials as well as place indent on the Administrative Body of the Dock Labour Board for listed labour for the purpose of unloading from the railway wagons as well as shore loading. Hence for the purpose of Iron ore handling, the workers of the Corporation, of the two handling agents M/s. T. K. Balasubramaniam and M/s. Western Agencies as well as the listed workers of the Administrative Body have been employed for doing more or less similar work solely in the Iron ore handling.

On 25-5-1973, the Corporation as well as M/s. C. K. Balasubramaniam and M/s. Western Agencies entered into Memorandum of Settlement with the Madras Port Dock Workers Congress under which the Mazdoors of the Employers agreed that they would forego the night shift allowance which was not then clearly admissible to the listed labourers in view of the increases in their wages. As a result, no night shift allowance was payable. However, after some pursuasion by the Union, M/s. C. K. Balasubramaniam agreed to pay the night shift allowance from 1-1-1974 and M/s. Western Agencies followed the same. But the Corporation refused to pay the night shift allowance and hence the Union approached the Assistant Labour Commissioner (Central), Madras for conciliation which however failed to materialise. Hence the Government referred the dispute to the Tribunal "whether the payment of night shift allowance from the 1st January '74 to the Tally Supervisors and Mazdoors engaged directly by MMTC, Madras is justified ? If so, to what relief are the workmen entitled".

To find out a solution to this difficult problem all the issues involved in the dispute were once against discussed among the parties hereto and the following agreement has been reached :

TERMS OF SETTLEMENT

The Corporation is agreeable to pay night shift allowance to Tally Supervisors from 17-5-1975 and to Mazdoors from 1-10-1975 and the workers agreed to the same.

The demands raised by the Madras Port and Dock Workers Congress under their letter dated 16-4-1975 are fully met by this settlement.

Signature of the Parties :
For The Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited.
Sd/- (S. K. AGARWAL)
General Manager.

For the Madras Port & Dock Workers Congress.
Sd/- (S. M. NARAYANAN)
General Secretary.

Witnesses :
1. Sd/-.....
2. Sd/-.....

T. PALANIAPPAN, Presiding Officer

[No. L-33011/2/75-D. IV(A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 27 जनवरी, 1976

का० आ० 1141.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन एयर लाइन्स के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या इंडियन एयर लाईंस, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र का श्री वाई एन० चतुर्वेदी सुरक्षा अधीक्षक, दम-दम विमान पत्तन को 14 दिसम्बर, 1974 से सेवा से हटाना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-11012(12)/75-डी० 2/बी]

हरबंस बहादुर अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 27th January, 1976

S.O. 1141.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Indian Airlines and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Indian Airlines, Calcutta are justified in removing Shri Y. N. Chaturvedi, Security Superintendent, Dum Dum Air Port from service with effect from the 14th December, 1974 ? If not, to what relief is the workman entitled ?

[No. L-11012(12)/75-D. II/B]

New Delhi, the 9th March, 1976

S.O. 1142.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Labour Court, Delhi in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Shri Om Prakash Assistant Wireman, Quarter No. E-1487, Netaji Nagar, New Delhi, which was received by the Central Government on the 4th March, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. LABOUR COURT, DELHI

Complt. No. 2 of 1975

Complaint U/s. 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947.
Shri Om Prakash, Asstt. Wireman, R/o Quarter No. E-1487, Netaji Nagar, New Delhi-23—Complainant.

VERSUS

Shri B. K. Basu, Executive Engineer (Elect.), Civil Construction Wing, All India Radio, Mandi House, New Delhi.— Respondent.

PRESENT :

Shri Inderjit Singh—for the management.

Shri Om Prakash Arora—workman in person.

AWARD

Shri Om Prakash Arora has filed this complaint under Section 33-A of the I. D. Act, 1947 against his transfer which he alleged was wrongful and by way of awarding him punishment.

2. The case of the complainant was that he was employed as an Asstt. Wireman in the Central Public Works Department and was confirmed as such. He was transferred on deputation to the A.I.R., New Delhi with effect from 1-11-73 for a period of two years with a right of exercising on option to be either permanently absorbed there or revert to the C.P.W.D. On 12-8-74, however, Shri B. K. Basu, the Executive Engineer (Elect.) Civil Construction Wing, A.I.R. New Delhi reported to the C.P.W.D., which he knowingly and wilfully mis-represented, as the complainant had never given his willingness/option in writing for repatriation to the C.P.W.D. He was even relieved of his duties on 23-4-75. On representation by him the orders of repatriation, which had been passed by the Superintendent Engineer, were kept in abeyance with the result that the complainant could not join duties in the C.P.W.D. Consequently, he had to remain on forced leave ever since 23-4-75. It was pleaded that the respondent's wilful mis-representation of facts caused the complainant heavy monetary loss of deputation allowance, which was admissible to him under an award of the Central Government Labour Court. It, also, seriously marred the bright chances of promotion in the A.I.R. It was further pleaded that the respondent bore him ill-will and wanted to wreck vengeance against him as he in the capacity of the Office bearer of the Union and a protected workman espoused the cause of other workmen, for claiming deputation allowance. It was, also, stated that the complainant had filed a complaint earlier, also, in this Court. It was withdrawn by him on the inference of the Shri I. K. Gujral Hon'ble Minister for Information and Broadcasting who ordered that the complainant would be allowed to join duty. The complainant was, however, transferred to penalise him to Vigyan Bhawan, New Delhi without allowing him to resume his duties at Centralised sub-station in the Broadcasting House, A.I.R., New Delhi where he worked formerly, as per the assurance of the Hon'ble Minister. It was prayed that this showed the pre-determination on the part of the respondent to get rid of him and to harass him by such transfer which was arbitrary, mala fide, and designed to coerce the complainant to seek repatriation. It amount to unfair labour practice and a contravention of the provisions of Sections 33-2(a) and (b) and Section 33-3(a) of the Industrial Disputes Act, 1947. He claimed the relief of being put on duty in the Centralised Sub-station, Broadcasting House, A.I.R., New Delhi till he exercised the option and full wages for the period of forced leave from 23-4-75.

3. The management raised the preliminary objections that the petition was not maintainable as there was no dispute pending under the Industrial Disputes Act, concerning the petitioner; that this Court had no jurisdiction to entertain the matter in dispute; and that the petitioner had no locus standi to file the petition in view of the fact that he was a permanent work-charged staff of the C.P.W.D. and no change in his service conditions was made. On merits it was admitted that the complainant was on deputation to the A.I.R., that Shri B. K. Basu reported to the C.P.W.D. that the complainant wanted to be repatriated; that he was relieved by the A.I.R.; and that the order of repatriation was held in abeyance. It was, also, admitted that the Hon'ble Minister intervened; and that the complainant was posted at Vigyan Bhawan in the capacity of an Asstt. Wireman. It was stated that the applicant failed to join the post and had been absenting since then. The allegations of mala fide, victimisation and coercion were denied. It was prayed that the complainant was not entitled to any relief.

4. The parties did not adduce any oral evidence. The complainant filed 13 documents which were all admitted by the Opposite Party. They were Ex. W/1 to Ex. W/13. The management produced 2 documents. They were admitted by the complainant and were Ex. M/1 and Ex. M/2.

5. Arguments were, then, heard.

6. The preliminary objection raised by the respondent that this Complaint did not lie and was not maintainable was decided by Order dated the 18th October, 1975. It was held that the complaint was maintainable.

7. The question that remains for decision is whether there was any contravention of the provisions of Section 33 of the Industrial Disputes Act, and what was the relief which the complainant was entitled to.

8. Section 33(2)(a) and (b) of the Act, contravention of which has been alleged, read as follows :—

33(2)....."During the pendency of any such proceedings in respect of an industrial dispute, the employer may, in accordance with the standing orders applicable to a workman concerned in such dispute, "or, where there are no such standing orders, in accordance with the terms of the contract, whether express or implied between him and the workman."

33(2)(a)..."alter, in regard to any matter not connected with the dispute, the conditions of service applicable to that workman immediately before the commencement of such proceeding; or

33(2)(b).."for any misconduct not connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise that workman :

Provided that no such workman shall be discharged or dismissed unless he has been paid wages for one month and an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of the action taken by the employer."

9. Thus, there would be contravention of Section 33(2)(a) or (b) only when the workman had been discharged or dismissed and had not been paid wages for one month and an application had not been made by the employer to the authority before which the proceedings in respect of an industrial dispute were pending, for approval of the action taken by the employer. Here in this case, there is no discharge nor dismissal. It is only a transfer; therefore, there is no contravention of the provision in Section 33(2)(a) or (b).

10. The complainant has, also, claimed contravention of Section 33(3)(a) and (b). It reads as follows :—

33(3)....."Notwithstanding anything contained in sub-section (2) no employer shall, during the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute, take any action against any protected workman concerned in such dispute—

33(3)(a)..."by altering, to the prejudice of such protected workman, the conditions of service applicable to him immediately before the commencement of such proceedings ; or

33(3)(b)..."by discharging or punishing, whether by dismissal or otherwise, such protected workman, save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.

11. The complainant has, however, failed to show that he was a protected workman. In order to be a protected workman in relation to an establishment, a workman (i) should be an officer of a registered Trade Union connected with the establishment, and he should have been recognised as such protected workman under the rules applicable to the establishment.

12. Rule 61 of the Central rules which deals with such recognition lays down that,

Rule 61...."Protected workmen..Every registered trade union connected with an industrial establishment to which the Act applies, shall communicate to the employer before the 30th September every year, the names and addresses of such of the officers of the union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the union should be recognised as "protected workmen". Any change in the incumbency of any such offer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change. (2).....The employer shall subject to S. 33, sub-section (4) recognise such workmen to be "protected workmen" for the purposes of sub-section (3) of the said section and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (i), the list of workmen recognised as protected workman."

13. The Complainant has filed only a certificate that he is a member of the Executive Committee (regional) of the C.P.W.D. Workers Union which is not addressed to anyone. It is, therefore, no communication to the employer, of the names and address of the officer of the Union who, in the opinion of the Union should be recognised as "protected workman". There is nothing to show, too, that the complainant had been recognised as a protected workman.

14. It is, therefore, held that the complainant not having been proved to be a protected workman, there was no contravention of Section 33(3)(a) and (b) of the Act.

15. The Complainant, then, urged that there was a contravention of Section 33(1)(a) and (b). This contention cannot be considered as it was not pleaded and if considered it would be making out a case for the Complainant by this Court which was not possible.

16. The total result is that there being no contravention of the Section 33(2)(a) and (b) nor of Section 33(3)(a) and (b) the very complaint is incompetent. The Complainant would be better advised to seek his relief by raising an industrial dispute under Section 10 of the Act. He is not entitled to any relief herein. An award is made accordingly.

D. D. GUPTA, Presiding Officer.

19th January, 1976.

[No. L-42014/1/76-D-II(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1976

का०आ० 1143.—कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ग की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यासी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, कोयला खान भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम कोयला खान भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला खान भविष्य निधि कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1964 की अनुसूची II में, पैरा 3 में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के सामने, स्तम्भ 4 में, (i) और (ii) प्रविष्टियों को (ii) और (iii) प्रविष्टियों के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(i) भविष्य निधि निरीक्षक

(चयन श्रेणी)"

[सं० ए०/12018(4)/75-पी एफ 1]

New Delhi, the 28th February, 1976

S.O. 1143.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3C of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act 1948 (46 of 1948) the Board of Trustees, with the approval of the Central Government, make the following regulations further to amend the Coal Mines Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1964, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Coal Mines Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II to the Coal Mines Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1964, in paragraph 3, in the Table, against serial number 2, in column 4, entries (i) and (ii) shall be renumbered as entries (ii) and (iii) and before the entries as so renumbered, the following entry shall be inserted, namely:—

"(i) Provident Fund Inspector (Selection Grade)".

[No. A. 12018(4)/75-PFI]

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1976

का०आ० 1144.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3468 तारीख 17 दिसम्बर, 1974 के अनुक्रम में दी भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 22 जनवरी, 1976 से 30 जून, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिये छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उसकी ओर से दी जानी थीं।

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गये थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिये गये उन फायदों को पाने के अब भी हकदार बने हुए हैं जो ऐसे फायदे हैं जिनके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन किया गया था, प्रयोजनार्थ:

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करने कि वह उसे ऐसी सूचना दे जो वह आवश्यक समझे; यह

(ख) ऐसे प्रदान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करेगा कि लेखे बहियां और अन्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजक और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने के या उसे ऐसी जानकारी दे, जिसे वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्त्ता या सेवक, या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गये किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करने; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये किसी रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज की प्रतियां तैयार करे या उससे उद्धरण लेने, के लिये शक्तिमान होगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के मंजूरी संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में समय लगा। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट के लिये पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस-38017(6)/73-एच० आई०]

New Delhi, the 1st March, 1976

S.O. 1144.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3468 dated the 17th December, 1974 the Central Government hereby exempts the Bharat Heavy Plates and Vessels Limited, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, from the operation of the said Act for a further period with effect from the 22nd January, 1976 upto and inclusive of the 30th June, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the proposal for grant of exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017(6)/73-H.I]

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1976

का०आ० 1145.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा की 1 उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 28 मार्च, 1976 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

कटक के जिले में पुलिस चौकी और तहसील सुकिन्दा में रामपास, सत्कानिया, जोदाबार और मोउण्डामल के राजस्व ग्रामों को शामिल करने वाले क्षेत्र।

[फा० सं० एस-38013/8/75-एच० आई०]

New Delhi, the 2nd March, 1976

S.O. 1145.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th March, 1976, as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa, namely :—

"Area comprising the revenue villages of Rampas, Satkania, Jodabar and Moundamal in Police Station and Tehsil Sukinda in the District of Cuttack."

[F. No. S-38013/8/75-HI]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1976

का०आ० 1146.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 643 तारीख 5 फरवरी, 1975 के अनुक्रम में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के (1) विमानन ईंधन केन्द्र बंगलौर वायुपत्तन, बंगलौर और (2) विमानन ईंधन केन्द्र, बेगमपेट वायुपत्तन, हैदराबाद को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 22 फरवरी, 1976 से 21 फरवरी 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिये छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उसकी ओर से दी जानी थी।

(2) नियम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गये थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिये गये उन फायदों को पाने के अब भी हकदार बने हुए हैं जो ऐसे फायदें हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन किया गया था, प्रयोजनार्थ:

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करने कि वह उसे ऐसी सूचना दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधान कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करेगा कि लेखे बहियां और अन्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, ऐसे निरीक्षक या अन्य

पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने के या उसे ऐसी जानकारी दे, जिसे वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गये किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करने; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की प्रतियां तयार करे या उससे उद्धरण लेने, के लिये सशक्त होगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के मंजूरी संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में समय लगा तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट के लिये पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस-38014(18)/74-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव

New Delhi, the 6th March, 1976

S.O. 1146.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 643, dated the 5th February, 1975 the Central Government hereby exempts (1) Aviation Fuel Station, Bangalore Air Port, Bangalore and (2) Aviation Fuel Station Begumpet Air Port, Hyderabad, belonging to the Indian Oil Corporation Limited from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 22nd February, 1976 upto and inclusive of the 21st February, 1977

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Empoyees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Empoyees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate empoyer at any reasonable time and require any person found incharge there of to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any persons whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the proposal for grant of exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/18/74-H.I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1976

का०आ० 1147.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट, सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण में या भवन कार्यों में, पत्थर तोड़ने और पत्थर कूटने में, भवनों के अनुरक्षण में, और धावनपथों (रनवे) के निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को देय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित प्रस्थापनायें इसके द्वारा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा यथाअपेक्षित, प्रकाशित की जाती है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पचहत्तर दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

अनुसूची

काम का प्रवर्ग	प्रतिदिन मजदूरी की सर्वग्राही न्यूनतम दरें				
	क्षेत्र क	क्षेत्र ख-1	क्षेत्र ख-2	क्षेत्र	क्षेत्र घ
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1	2				
अकुशल					
(1) बजरी बिछाने वाला (2) बेलदार (व्यस्थ पुरुष/आदमी; व्यस्य स्त्री/महिला; किशोर/12 वर्ष से ऊपर के लड़के, लड़कियां; बालक) (3) बीटर महिला; (4) धोंकनीवाला (5) जरीबी (6) केवट (7) बाल्टीवाला (8) वाहक पत्थर (9) वाहक (पानी) (10) गाड़ीवान (11) केयरटेकर (पुल) (12) क्लीनर (रेल-पथ; राख गर्त के लिये सिन्डर) (13) चौकीदार (14) कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला) (15) दफादार (16) चालक (बैल, ऊंट, गधा, पिट्टू) (17) झंडीवाला (18) झंडी वाला (बैलास्ट ट्रेन) (19) गेटमैन (20) गैंगमैन (21) गैंग मैन (रेल पथ) (22) हैंडलमैन (23) जम्परमैन (24) कमीन (महिला कार्य) (25) खलासी (26) खलासी (आदमी/पुरुष; नारी/महिला; लड़के/लड़कियां; I/II; पुल, वैद्युत; समुद्री; मोपला; तट; भण्डार; स्टीम रोड रोलर; सर्वेक्षण) (27) श्रमिक (बाग) (28) बत्तीवाला (29) माली (30) मजदूर (31) मजदूर (व्यस्य पुरुष/नर; व्यस्थ महिला/नारी) (32) मजदूर (किशोर/12 वर्ष की आयु से ऊपर के लड़के; लड़कियां; बालक; लौरी; प्रशिक्षित) (33) पैट्रोलवाला (34) चपरासी (35) तलाशीकर्ता (36) सिगनल मैन (37) स्ट्राइकर (38) स्ट्राइकर (मोपलागिंग) (39) झाड़कश (40) टट्टी बॉय (41) टाइल टर्नर (42) ट्राली वाला (43) वाल्व नियंत्रक (44) वाल्वमैन (45) प्रहरी (46) पानीवाला (47) सफेदीवाला (48) वुडरमैन (49) वुडखुमैन (50) बारीमैन (51) कोयलेवाला (52) कंडेन्सर परिचर (53) घास काटने वाला (54) मुछेर जमादार (55) स्लिंगर (56) शंटर (57) अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों, चाहे ये किसी भी नाम से पुकारे जाएं	6.50	5.95	5.40	4.90	4.45
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी					
(1) बेलचावाला (2) भिश्ती (3) भिश्ती (मुश्क सहित) (4) नाववाला (प्रधान) (5) तोड़क (6) तोड़क (चट्टान; चट्टानी पत्थर; प्रस्तर धातु; पत्थर) (7) बेंत बुनने वाला (8) जरीबी (प्रधान) (9) चारपाई कसने वाला (10) जांच पड़ताल कर्त्ता (11) चौकीदार (12) कैकर (13) दफ्तरी (14) डालीमैन (15) (15) ड्रिमर (16) ड्रिलर (छिद्र; चट्टान) (17) चालक (स्किन) (18) उत्खनक (19) फेरीवाला (20) फायरमैन (21) फायरमैन (ईंटों का भट्टा; स्टीम रोड रोलर) (22) द्वाररक्षक (23) घरामी (थैचर) (24) शीशेवाला (25) ग्रीसर (26) ग्रीशर-एवं-फायरमैन (27) ग्राइंडर (28) हथौड़ेवाला (29) सहायक (कारीगर) (30) सहायक (आराकश) (31) जमादार (32) कोभैन (33) खलासी (प्रधान सर्वेक्षण; सिवेटर्स-मोपलागिंग; पर्यवेक्षक) (34) श्रमिक (चट्टान कर्त्तन) (35) लस्कर (36) माली (प्रधान) (37) मेट (38) मेट (लौहकार; सड़क; काष्ठकार; इंजीनियर चालक और/या फीडर फिटर; गैंग; खलासी; मजदूर; राज; रेल पथ; पम्प ड्राइवर; टर्नर) (39) मजदूर (हैवी वेट; चार्जमैन; मिस्त्री; प्रधान) (40) मुकदम (41) रात्रि-गार्ड (41-क) हरकारा (डाक) (42) तेलवाला (43) खदानकार (44) खदान प्रचालक (45) भण्डारवाला (46) स्टोकर (47) स्टोकर (और वायलमैन) (48) थैचर (49) धूम्बामैन (स्पेडमैन) (50) टिंडल (51) ट्रॉलीवाला (रोड; मोटर) (52) फिटर (महायक अर्द्धकुशल) (53) जमादार (अर्द्धकुशल) (54) मेट (भण्डार) (55) पम्प परिचर (56) वाहक (57) ब्रेकसमैन (58) ओव्हरमैन (59) रसोइया (60) डाण्डी (61) फराश (62) हैक्सामैन (63) सहायक (लोको-क्रेन/ट्रक) (64) कसाब (65) खलासी (संरचनात्मक) (66) प्रयोगशाला परिचर (67) मांझी (नाववाला) (68) मशालची (69) पी० एम० मेट्स (70) प्वाइण्ट्समैन (71) सीकमी (72) टोपाज (73) तोपकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला) (74) ट्रॉली जमादार (75) विंचमैन (76) अन्य कोई प्रवर्ग, जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हैं चाहे ये किसी भी नाम से पुकारे जायें, ...	8.12	7.44	6.75	6.12	5.56

1	2
कुशल	
(1) सहायक मिस्त्री (2) आर्मेचर वाइंडर श्रेणी II और III (3) भण्डारी (4) लौहकार (चयन श्रेणी; श्रेणी II,III; वर्ग II और III; प्रधान) (6) बायलरमैन (7) बॉयलर मैन (श्रेणी II और श्रेणी III) बायलर फोरमैन श्रेणी II (9) भण्डारी (10) ब्रिकलेयर (11) ब्रिकलेयर (चयन श्रेणी; वर्ग II) (12) विस्फोटक (13) काष्ठकार (14) काष्ठकार (चयन श्रेणी; श्रेणी II और III; वर्ग I और III; सहायक; बी० आई० एम० रोड) (15) कैबिनेट बनाने वाला (16) बेंतवाला (17) सेलोटेक्स कटर मेकर (18) चार्जमैन वर्ग II; और वर्ग III (19) काष्ठकार (साधारण) (20) जांच-पड़ताल-कर्त्ता (कनिष्ठ) (21) चिक बनाने वाला (22) चिकवाला (23) कंक्रीट मिश्रण मिश्रक (24) कंक्रीट मिश्रक प्रचालक (25) मोची (26) गुल्ली निर्माता (27) चालक (28) चालक (मोटर; यान; मोटर यान चयन श्रेणी; मोटर लारी; मोटर लारी श्रेणी II; मोटर; डीजल इंजन; डीजल इंजन श्रेणी II; यांत्रिक मिश्रक; रोड रोलर आई० सी० और सीमेंट मिश्रक आदि रोडरोलर (29) रोड रोलर चालक श्रेणी II (30) चालक/इंजन स्टेटिक; स्टोन क्रशर; ट्रैक्टर/बुलडोजर; स्टीम रोड रोलर; जल पम्प यांत्रिक; सहायक रोड रोलर; यांत्रिक; स्टीम क्रेन; बुलडोजर सहित ट्रैक्टर यांत्रिक परिवहन; इंजन; स्थैतिक और सड़क बेलन; बायलर परिचर; इंजीनियर) (31) प्रचालक (स्टोन क्रशर यांत्रिक) (32) डिस्टेम्पर करने वाला (33) बिजली मिस्त्री (श्रेणी II; वर्ग II) (35) फिटर (36) फिटर (चयन श्रेणी; श्रेणी II; III; वर्ग II; III; सहायक, पाइप; पाइप वर्ग II; पाइप लाइन; कुमुक के लिये छड़ें मोड़ना एवं यांत्रिक; यांत्रिक; और पलम्बर) (37) घरामी (प्रधान) (38) ग्लेजियर (39) विस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर (40) जायनर (41) जायनर (केवल; श्रेणी II) (42) लाइनमैन (श्रेणी II; III; एच टी/एल टी) (43) राज (44) राज (चयन श्रेणी; श्रेणी II और श्रेणी III; वर्ग II और III; वर्ग ख मिस्त्री; स्टोन; स्टोन; वर्ग II; ईंट का काम; पत्थर का कार्य; ब्रिकलेयर; टाइल-फ्लोरिंग; बी० टी० एम० मुक्कदम; प्रधान, पत्थर कर्त्तन; साधारण) (45) मशीन मिस्त्री (46) यांत्रिक (47) यांत्रिक (वर्ग II; वातानुकूलन; वातानुकूलन श्रेणी II; डीजल श्रेणी II; रोड रोलर श्रेणी II; सहायक; रेडियो) (48) राज (घरामी) (49) मिस्त्री (50) मिस्त्री (श्रेणी II; वातानुकूलन श्रेणी II; रेल-पथ; सर्वेक्षण; सान्द्रारा: संकर्म) (51) राज वर्ग क (52) सांचागार (53) सांचागार (ईंट: टाइल) (54) रंगसाज (55) रंगसाज (चयन श्रेणी : श्रेणी II और III : वर्ग II : सहायक : लाटर : और पालिशगर; पालिशगर; रफ) (56) प्लास्टर कर्त्ता (57) प्लास्टर कर्त्ता (राज श्रेणी II) (58) नलसाज (59) नलसाज (चयन श्रेणी : वर्ग 2 : सहायक ज्येष्ठ कनिष्ठ; मिस्त्री श्रेणी II) (60) नलसाज मिस्त्री (61) नलसाज-एवं-फिटर (62) पालिशगर (63) पालिशगर (फर्श) (64) पम्प चालक (65) पम्प चालक (चयन श्रेणी; श्रेणी 2 और 3; वर्ग II) (66) पम्प (इंजन चालक) (67) पी० ई० चालक (68) पम्पवाला (69) पम्पवाला (सहायक) (70) पम्पर (71) पालिशगर (स्प्रे सहित) श्रेणी II (72) रटनमैन (73) रिवेट कर्त्तक (सहायक) (74) रिवेटकार (75) रिवेटकार (कर्त्तक) (76) सड़क निरीक्षक श्रेणी II (77) रेलवे प्लेटलेयर (78) रोड बाइन्डर (79) आराकश (80) आराकश (चयन श्रेणी वर्ग II) (81) सेरंग (82) सेरंग पाइल ड्राइविंग पैन्ट्स बायलर सहित (83) सनेप्समैन (84) पारी भारसाधक (85) स्प्रेमैन (86) स्प्रेमैन (रोड्स) (87) संगतराश (88) संगतराश (चयन श्रेणी : श्रेणी II; वर्ग II) (89) स्टोन चिजेलर (90) पाषाण चिसलर (वर्ग 2) (91) पाषाण विस्फोटक (92) उप ओवरसियर (अन-हित) (93) सर्वेक्षक (94) सर्वेक्षक (सहायक) (95) दर्जी (96) दर्जी (पोशिश) (97) तार स्प्रेयर (98) तारमैन (99) लाइनमैन (100) टाइलर (वर्ग 2 : दीवार; फर्श : छत) (101) टाइलर (चयन श्रेणी) (102) टीनकार (103) टीनकार (चयन श्रेणी : श्रेणी II : और III; वर्ग II) (104) टीनकार (105) ट्रेलर्स (106) टर्नर (107) पोशिशसाज (108) पोशिशसाज (श्रेणी II और श्रेणी III) (109) रंगसाज स्प्रे वर्ग II (110) काष्ठ कर्त्तक (111) काष्ठ कर्त्तक चयन श्रेणी (112) काष्ठ कर्त्तक वर्ग II (113) वर्क सरकार (114) झलाइगर (115) गैस झलाइगर (116) झलाइगर (वर्ग II : पुल कार्य) (117) कुआं खोदने वाला (118) सफेदी वाला	

1	2				
(119) सफेदीवाला (चयन श्रेणी : वर्ग II) (120) तारमिस्त्री (121) तारमिस्त्री (श्रेणी II और III : वर्ग I : यांत्रिक; वैद्युत) (122) सफेद पुताई और रंगीन पुताई वाला (123) वातिक औजार प्रचालक (124) प्रचालक (फिटर) (125) बोरमैन (126) बेधक (127) छिलाईकार (128) छिलाईकार-एवं-पिसाईकार (129) रसोइया (प्रधान); (130) ड्रिलर (कूआ बोरिंग) (131) चालक (लोको/ट्रक) (132) बिजली मिस्त्री (सहायक) (133) यांत्रिक (नलकूप) (134) मिस्त्री (इस्पात : नलकूप; टेलीफोन) (135) मीटर वाचक (136) मौसम प्रेक्षक (137) नावधानी (138) प्रचालक (वैचिंग संयंत्र); सिनेमा परियोजना; क्लम्प शैल : संपीडित्र; केन, डेरिक : डीजल ईंजन : डोजर; ड्रैगलाइन : ड्रिल : डम्पर : उत्खनक : फोर्क लिफ्ट : जनित्र : ग्रेडर; हैक हैम्पर और पटरी तोड़ने वाला; लोडर; पम्प; पाइल चालन; स्क्रैपर : स्क्रीनिंग संयंत्र : शावेल : ट्रैक्टर; वाइब्रेटर : वे-बैचर (139) रेल गार्ड (140) मरम्मतकर्त्ता (बैटरी) (141) शार्पर/स्लोटर (142) स्प्रेयर (ग्रस्फाल्ट) (143) स्टेशन मास्टर (144) सर्वेक्षक (सिस्ट) (145) दस्तकार (146) गाड़ी परीक्षक (147) टर्नर/मिलर (148) टायर वालकैनाइजर (149) कार्य (सहायक) (150) कोई अन्य प्रवर्ग जो कि कुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें	10.40	9.52	8.64	7.84	7.12
अत्यधिक कुशल					
(1) आर्मेचर वाइंडर श्रेणी I (2) लौहकार श्रेणी I और वर्ग I (3) बायलरमैन श्रेणी I (4) बायलर मैन फोरमैन श्रेणी I (5) ब्रिक लेयर (6) केबल संयोजक श्रेणी I (7) काष्ठकार श्रेणी I और वर्ग I (8) सेलोटेक्स कटर और सजावटकर्त्ता (9) चार्जमैन वर्ग I (10) जांच-पड़ताल कर्त्ता (ज्येष्ठ) (11) चालक लोरी श्रेणी I; मोटर लारी श्रेणी I; मोटरयान वर्ग I और डीजल ईंजन श्रेणी I; रोड रोलर श्रेणी I; पम्प श्रेणी I वर्ग I (12) इलैक्ट्रीसीयन ग्रेड I श्रेणी I (13) फिटर (श्रेणी I; वर्ग I ; पाइप वर्ग I; (प्रधान) (14) फोरमैन (सहायक) (15) लाइनमैन श्रेणी I (16) राज (कुशल श्रेणी I; वर्ग I) (17) मास्ट रिगर यांत्रिक वर्ग I और वर्ग II (18) यांत्रिक (प्रधान) या बिजली मिस्त्री (19) यांत्रिक (डीजल श्रेणी I; रोड रोलर श्रेणी I; वातानुकूलन श्रेणी I; वर्ग I; वातानुकूलन (20) मिस्त्री श्रेणी I (21) मिस्त्री (वातानुकूलन श्रेणी I) (22) ओवरसियर (23) ओवरसियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) (24) रंगसाज (श्रेणी I; वर्ग I; स्प्रे) (25) प्लास्टरकर्त्ता (मिस्त्री वर्ग I) (26) नलसाज (प्रधान) वर्ग I; मिस्त्री श्रेणी I (27) पॉलिशगर (छिड़कनी सहित) श्रेणी I (28) सड़क निरीक्षक श्रेणी I (29) आराकश वर्ग I (30) संगतराश श्रेणी I (31) संगतरास कर्ता श्रेणी I (32) स्टोन क्विजकर वर्ग I (33) पाषाण मिस्त्री I (34) उपओवरसियर (अहिंस) (35) टाइलर वर्ग I (36) टीनकार श्रेणी I और वर्ग I (37) पोशिशसाज श्रेणी I (38) वार्निशकार वर्ग I (39) ब्लाईगर-एवं-फिटर और वातानुकूलन यांत्रिक (40) ब्लाईगर (गैस) वर्ग I (41) सफेदी नाला वर्ग I (42) वायरमैन श्रेणी I; वर्ग I (43) काष्ठकर्त्तक वर्ग I (44) पिसाईकार (औजार) श्रेणी I (45) प्रचालक (वैचिंग प्रचालक) श्रेणी I; क्लैम्प शेल श्रेणी I; संपीडित्र श्रेणी I; क्रेन श्रेणी I डीजल ईंजन श्रेणी I; ड्रिल श्रेणी I डम्पर श्रेणी I; उत्खनक श्रेणी I; फोर्क लिफ्ट श्रेणी I; जनित्र श्रेणी I; ग्रेडर श्रेणी I; लीडर श्रेणी I पाइल ड्राइविंग श्रेणी I; पम्प श्रेणी I; स्क्रैपर श्रेणी I; स्क्रीनिंग संयंत्र श्रेणी I; शावेल श्रेणी I; शावेल और ड्रैगलाइन; ट्रैक्टर श्रेणी I; वाइब्रेटर श्रेणी I; रिगर श्रेणी I; रिगर श्रेणी II (46) शार्पर/स्लेटर श्रेणी I (47) दस्तकार वर्ग I (48) टर्नर/मिलर श्रेणी I (49) टायर वालकनाइजर श्रेणी I (50) कार्य (सहायक) श्रेणी I (51) कोई अन्य प्रवर्ग जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं। चाहे किसी भी नाम से पुकारे जायें।	13.00	11.90	10.80	9.80	8.90
लिपिकीय					
(1) एम० सी० लिपिक (2) मुंशी (मैट्रिकुलेट; नॉनमैट्रिकुलेट) (3) भण्डार लिपिक (मैट्रिकुलेट ; नॉनमैट्रिकुलेट) (4) भण्डार निर्गमकर्त्ता (5) भण्डार लिपिक (6) भण्डार रक्षक (श्रेणी I, II ; मैट्रिकुलेट II ; नॉनमैट्रिकुलेट) (7) मिसलान लिपिक (8) समयपाल (मैट्रिकुलेट ; नॉनमैट्रिकुलेट) (10) औजार कीपर (11) कार्य मुंशी (12) कार्य मुंशी (अधीनस्थ) (13) लेखा लिपिक (14) लिपिक (15) संगणक (16) टेलीफोन प्रचालक (17) टंकक (18) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे जिस नाम से पुकारे जाएं, जो कि लिपिकीय प्रवृत्ति के हों।	10.40	9.52	8.64	7.84	7.12

1	2	3	4	5	6

(स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,—

(1) क्षेत्र क, ख 1, ख–2 और ग में इस अधिसूचना के उपाबन्ध I में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट हैं जिनमें नगर निगम या नगर पालिका या छावनी बोर्ड की परिधि से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले सभी स्थान सम्मिलित हैं ; और क्षेत्र, 'घ' में वे सभी स्थान हैं जो क, ख,–1, ख–2 और ग क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं हैं ।

(2) 'घ' वर्ग के क्षेत्रों में, जहां न्यूनतम मजदूरी क्षेत्रवार आधार पर नियत की गई है और जहां केन्द्रीय सरकार ने सर्दी /पर्वतीय और अन्य विशेष भत्ते का संदाय मंजूर किया हो, अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों को, उन्हें देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन नियत या पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी से दस प्रतिशत अधिक संदत्त किया जाएगा ।

(3) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना के अधीन नियत मजदूरी यदि, राज्य सरकार द्वारा ऐसे तत्सम अनुसूचित रोजगार के लिए, जिसके लिए वह समुचित सरकार है, नियत मजदूरी से कम हो तो उच्चतर दरें इस अधिसूचना के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों के रूप में देय होंगी ।

(4) (क) अकुशल कार्य वह है, जिसमें बहुत थोड़े या कुछ भी कुशलता या कार्य के अनुभव की अपेक्षा न रखने वाली साधारण संक्रियाएं सम्मिलित हैं –

(ख) 'अर्द्ध-कुशल' कार्य वह है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं तथा इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) "कुशल" कार्य वह है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा किसी एक शिल्प के रूप में या किसी तकनीकी या व्यवसायी संस्थान में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके निर्वहन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ;

(घ) "अत्याधिक कुशल" कार्य वह है जिसमें कतिपय कार्यों के करने में सघन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या कई वर्ष के कार्य के व्यावहारिक अनुभव द्वारा अर्जित उच्च कोटि की पूर्णता और पूर्ण सक्षमता आवश्यक है और कर्मकार से यह भी अपेक्षित है कि वह इन कार्यों के निष्पादन में अन्तर्वलित निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण दायित्व ले ।

(5) मजदूरी की न्यूनतम दरें संविदाकारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होती हैं ;

(6) मजदूरी की न्यूनतम दरों में सभी सर्वसमावेशी दरें आती हैं और उसमें विश्राम के साप्ताहिक दिवस के लिए मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(7) 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा व्यक्तियों और निशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें, समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकार को देय दरों का 70 प्रतिशत होंगी ।

उपाबन्ध I

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	नगरों		उपनगरों का वर्ग	
	क	ख-1	ख-2	ग
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	—	—	एडोनी, अंकापाले, अनन्तपुर बोदार (मसूली-पटनम), भीमावरम, चिराला, चित्तूर कुडुपा, एलूरु, गुडीवडा, गुन्टाकल, गुन्तुर, काकी नाडा, खम्माम, कोथागुदम, कुरनूल, महबूबनगर, नन्दयाल, नेल्लोर, निजामाबाद, ओंगोल, प्रोद्दातुर, राजाहमुन्दरी, तेनाली, तिरुपति विजापुरी, विजयवाड़ा (बेजवाड़ा) विशाखापत्तनम (विजायापटम), विजयानगरम, वारंगल ।
बिहार	—	—	पटना, धनबाद, जमशेदपुर	आरा, बेतियाह, भागलपुर, बिहार शरीफ़ बोकारो स्टील सिटी, छपरा, दरभंगा, दीनापुर, गया, हजारीबाग, कटिहार, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रांची ।
चण्डीगढ़	—	—	—	चण्डीगढ़
दिल्ली	—	—	—	
गुजरात	—	अहमदाबाद	सूरत, वडोदरा (बड़ौदा)	आनन्द, भावनगर, भुज, भड़ौच, कम्बे, धोराजी, गोध्रा, गोडल, जामनगर, जूनागढ़, कलोल, मेहसाना, मोरवी, नाडियाड, नवसारी, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, वीरावल ।

1	2	3	4	5
हरयाणा	—	—	—	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर ।
कर्नाटक	बंगलौर	—	—	बागलकोट, बेलगांव, बेलरी, भद्रावती, बीदार, बीजापुर, चित्रदुर्ग, दावणगीर, गड़ग-बेटगरी, गुलबर्गा, हसन, होस्पेट, हुबली धारवाड़, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, मण्डया, मंगलौर, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर ।
केरल	—	—	कोचीन, त्रिवेन्द्रम	अलेप्पी, बदागर, कालीकट, (कोझी कोड), कनोनेर, कयामकुलम कोट्टमय, पालघाट, तेलीचेरी, त्रिचुर, क्विलोन ।
मध्य प्रदेश	—	—	इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर	भिलाई नगर, औद्योगिक उपनगर, भोपाल, बिलासपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, दुर्ग, (लश्कर) खण्डवा, मंदसौर, महू (छावनी), मुड़वारा, रायपुर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन ।
महाराष्ट्र	मुम्बई	नागपुर पुणे	शोलापुर	अचलपुर, उपनगर समूह, अहमदनगर, अकोला, अमलनेर, अम्बरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसी भिवंडी, भुसावल, चांदा, चन्द्रपुर, भुलिया, दोम्बीवली, गोदिया, इचलकरंजिया, जलगांव, जलना, कल्याण, कैम्पटी, खामगांव, कोल्हापुर, लातुर, मालेगांव, नानंदेड, नन्दुरबार, नासिक, नासिक मार्ग, देवलाली, पण्ढरपुर, परभानी, पिम्परी-चिंचवाड़, सांगलमिराज, सतारा, उल्हासनगर, यवतमाल, वर्धा ।
उड़ीसा	—	—	—	बिरहामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, राउरकेला, सम्बलपुर ।
पांडिचेरी	—	—	—	पांडिचेरी ।
पंजाब	—	—	अमृतसर, लुधियाना	अबोहर, बटाला, भटिंडा, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा ।
राजस्थान	—	—	जयपुर	अजमेर, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर ।
तमिलनाडु	मद्रास	—	कवायम्बतूर, मदुराई, सालेम तिरुचिरापल्ली (त्रिचिनोपोली)	अम्बुर, अरुप्पुकोट्टई, बोदी नायकनुरे, कुडालोर, डिंडीगुल, एरोड, गुडियाथम, कदायानल्लुर, कुम्बकोनम, मयूरम, नागापट्टीनम, नागरकोयल, पलायमकोट्टई, पोलच्ची, पुडुकोट्टई, राजापलयम, श्रीरंगम, श्रीवलीपुत्तुर, साम्बरम, थंजावुर (तंजौर) तिरुनेलवेली, तिरुप्पुर, तिरुवन्नामलाई, तूतीकोरिन, बालपराई, वनियाम्बदी, वेलोर, विलुपुरम, विरुद्ध नगर ।
उत्तर प्रदेश	—	कानपुर, लखनऊ	आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी (बनारस)	अलीगढ़ (कोयल अलीगढ़), अमरोहा, बहराइच बांदाइ बरेली, बदायूं, बुलन्दशहर, चंदौसी, देहरादून, इटाव फैजाबाद,-एवं-अयोध्या, फर्रुखाबाद-एवं-फतेहगढ़, फतेहपुर फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हल्द्वानी-एवं-काठगोदाम, हापुड़, हरिद्वार,

1	2	3	4	5
				हाथरस, जौनपुर, झांसी, खुर्जा, मथुरा, मउनाथभंजन, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, रुड़की, सहारनपुर, सम्भल, शहजहांपुर, सीतापुर ।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	—	—	आसनसोल, बैद्यवती, बाली, बनगांव, बंकुरा, बांसबेरिया, बारकपुर, बशीरहाट, बेरहामपुर, भाटपारा, बज बज, बर्दवान, खाम्पदानी चन्दरनगर, कूचबिहार, दुर्गापुर, हुगलिश बाजार, हाली शहर, हुगली-चिनसुरा, जलपाईगुड़ी, कमरहटी, कंचरापारा, खड़गपुर, कृष्णनगर, मिदनापुर, नवाबद्वीप, नैहाटी, उत्तरीदमदम, पानी हाटी, पुरुलिया, रिशरा, शान्तिपुर, सेरामपुर, सिलीगुड़ी, टीटागढ़, उत्तरपारा, कोटरंग ।

[सं० 32019(18)/75-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

हंसराज छाबरा, उप-सचिव

New Delhi, the 2nd March, 1976

S.O. 1147.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4, of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for revising the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule, annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employments in the construction or maintenance of roads or in building operations in stone breaking and stone crushing, in the maintenance of buildings, and in the construction and maintenance of runways, specified in the corresponding entries in column 1 of the said schedule, are hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said proposals will be taken into consideration on or after the expiry of seventy-five days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Category of work	All inclusive minimum rates of wages per day				
	Area A	Area B-1	Area B-2	Area C	Area D
1	2				
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
UNSKILLED :					
(1) Bajri Spreader (2) Beldar (Adult Male/Man; Adult Female/Women; Adolescent/Boys above 12 years, Girls; Child) (3) Beater Woman (4) Bellowman (5) Chain Man (6) Boad Man (7) Bucket Man (8) Carrier (Stone) (9) Carrier (Water) (10) Cart Man (11) Caretaker Bridge (12) Cleaner (Crane Track; Cinder for Ash Pit) (13) Chowkidar (14) Concrete (Hand Mixer) (15) Daffadar (16) Driver (Bullock; Camel, Donkey, Mule) (17) Flag Man (18) Flagman (Balast Train) (19) Gate Man (20) Gangman (21) Gang Man (Permanent Way) (22) Handle Man (23) Jumper man (24) Kamin (Female work) (25) Khalasi (26) Khalasi (Man/Male; Woman/Female; Boys/Girls; I/II; Bridge, Electrical; Marine; Moplah; Shore; Store; Steam Road Roller; Survey) (27) Labourer (Garden) (28) Lamp Man (29) Mali (30) Mazdoor (31) Mazdoor (Adult Male/Man; Adult Female/Women) (32) Mazdoor (Adolescent/Boys above 12 years age; Girls; Child; Lorry; Trained) (33) Petrolman (34) Peon (35) Searcher (36) Singal Man (37) Strikers (38) Striker (Moplah Gang) (39) Sweeper (40) Tatti Boy (41) Tile Turner (42) Trolly Man (43) Valve Controller (44) Valveman (45) Watchman (46) Waterman (47) White Washer (48) Wooderman (49) Wooder Women (50) Borryman (51) Goal man (52) Condenser Attendant (53) Grass cutter (54) Muchhers Jamadars (55) Slingers (56) Shunters (57) Any other categories by whatever name called which are of an unskilled nature.	6.50	5.95	5.40	4.90	4.45
SEMISKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY :					
(1) Belchawala (2) Bhisti (3) Bhisti (with Mushk) (4) Boatman (Head) (5) Breaker (6) Breaker (Rock; Rock stone; Store Metal; Stone) (7) Cane Weaver (8) Chain Man (Head) (9) Charpoy Stringer (10) Checker (11) Chowkidar (Head) (12) Gracker (13) Daftri (14) Dollyman (15) Driller (16) Driller (Hole; Rock) (17) Driver (Skin) (18) Excavator (19) Ferroman (20) Fireman (21) Fireman (Brick Kiln; Steam Road Roller) (22) Gate Keeper (23) Gharami (Thatcher) (24) Glass Man (25) Greaser (26) Greaser-cum-fireman (27) Grinder (28) Hammer man (29) Helper (Artisan) (30) Helper (Sawyer) (31) Jamadar (32) Keyman (33) Khalasi (Head Survey; Rivetters-Moplah Gang; Supervisor)					

(1)	(2)				
(34) Labourer (Rock-cutting) (35) Lascar (36) Mali (Head) (37) Mate (38) Mate (Blacksmith; Road; Carpenter; Engine Driver and or Feeder; Fitter; Gang; Khalasi; Mazdoor; Mason; Permanent Way; Pump Driver; Turner) (39) Mazdoor (Heavy-Weight; Charge-Man; Mistry; Head) 40) Muccadam (41) Night Guard (41A) Runner (Post dak) (42) Oil Man (43) Quarry Man (44) Quarry Operator (45) Store Man (46) Stocker (47) Stocker & (Boilman) (48) Thatoher (49) Thoombaman (Spade Worker) (50) Thindals (51) Trollyman (Road Motor) (52) Fitter (Asstt. Semi-skilled) (53) Jamadar (Semi-skilled) (54) Mate (Store) (55) Pump Attendant (56) Bearer (57) Brakesman (58) Crowbar Man (59) Cook (60) Dandee (61) Farash (62) Hacksaw Man (63) Helper (Locco-Crane/Truck) (64) Kasab (65) Khalasi (Structural) (66) Laboratory Boy (67) Manjee (Boatman) (68) Masalchi (69) P. M. Mates (70) Pointsman (71) Seacummy (72) Topaz (73) Topkar (Big Stone Breaker) (74) Trolly Jamadar (75) Watchman (76) Any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature.	8.12	7.44	6.75	6.12	5.56
SKILLED : (1) Asstt. Mistry (2) Armature Windez Grade II and III (3) Bhandari (4) Blacksmith (Selection Grad; Grade II; III; Class II & III; Head) (6) Boilerman (7) Boilerman (Grade II and III) (8) Boiler Foreman Grade (II) (9) Bhandari (10) Brick layer (11) Bricklayer (Selection Grade; Class II) (12) Blasterer (13) Carpenter (14) Carpenter (Selection grade; Grade II & III; Class I and III; Assistant; B.T.M. Road) (15) Cabinet Maker (16) Cameraman (17) Celotex Cutter Maker (18) Chargeman Class II; and Class III (19) Carpenter (Ordinary) (20) Checker (Junior) (21) Chick Maker (22) Chick Man (23) Concrete Mixture Mixer (24) Concrete Mixer Operator (25) Cobbler (26) Coremaker (27) Driver (28) Driver (Motor; Vehile; Motor Vehicle Selection Grade; Motor Lorry; Motor Lorry Grade II; Diesel Engine; Diesel Engine Grade II; Mixer Mechanical; Road Roller I.C. and Cement Mixer etc. Road Roller (29) Road Roller Driver Grade II (30) Driver (Engine Static; Stone Crusher; Tractor/Bull Dozer; Steam Road Roller; Water Pump Mechanical; Assistant Road Roller; Mechanical; Steam Crane; Tractor with Bull Dozer Mechanical Transport; Engine; Static & Road Roller; Boiler Attendant; Engine) (31) Operator (Stone Crusher Mechanical) (32) Distemperer (33) Electrician (34) Electrician (Grade II; Class II, Class III) (35) Fitter (36) Fitter (Selection Grade; Grade II; III; Class II; III; Assistant; Pipe; Pipe Class II; Pipe Line; Bending Bars for Reinforcement-cum-mechanic; Mechanic & Plumber; (37) Charami (Head) (38) Glazier (39) Hole Driller for Blasting (40) Joiner (41) Jointer (Cable Grade II) (42) Line Man (Grade II, III HT/Lt) (43) Mason (44) Moson (Selection Grade; Grade II;& III; Class II and III; Class B Mistry; Stone; Stone Class II; Brick Work Stone Work; Brick-layer; Tile Flooring; B.T.M.; Muccadam; Head; Stone Cutting; Ordinary) (45) Machinist (46) Mechanic (47) Mechanic (Class II; Air Conditioning; Air Conditioning Grade II; Diesel Grade II; Road Roller Grade II; Assistant; Radio) (48) Mason (Gharami) (49) Mistry (50) Mistry (Grade II; Airconditioning Grade II P. Way; Survey; Santras; Works) (51) Mason Class A (52) Moulder (53) Moulder (Brick; Tile) (54) Painter (55) Painter (Selection Grade; GradeII and III; Class II; Assistant; Lotter; & Polisher; Polisher; Rough) (56) Plasterer (57) Plasterer (Mason Grade II) (58) Plumber (59) Plumber (Selection Grade; Class II; Assistant Senior; Junior; Mistry Garde II) (60) Plumbing Mistry (61) Plumber-cum-Fitter (62) Polisher (63) Polisher (Flour) (64) Pump Driver (65) Pump Driver (Selection Grade; Grade II and III; Class II) (66) Pump (Engine Driver) (67) P.E. Driver (68) Pump Man (69) Pump Man (Asstt.) (70) Pumper (71) Polisher (with spray) Grade II (72) RatanMan (73) Rivet Cutter (Asstt.) (74) Rivetter (75) Rivetter, (Cutter) (76) Road Inspector Grade II (77) Railway Plate Layer (78) Rod Binder (79) Sawyer (80) Sawyer (Selection Grade Class II) (81) Serang (82) Serang-pile Driving Pantooms with Boiler (82) Shapsman (84) Shift-in-charge (85) Sprayman (86) Sprayman (Roads) (87) Stone Cutter (88) Stone Cutter (Selection Grade; Grade II; Class II) (89) Stone Chisler (90) Stone Chisler (Class II) (91) Stone Blasterer (92) Sub-Overseer (unqualified) (93) Surveyers (94) Surveryors (Asstt.) (95) Tailor (96) Tailor (upholstry) (97) Tar Spayer (98) Tar Man (99) Line Man (100) Tiler (Class II; Wall; Floor; Roof) (101) Tiler (Selection Grade) (102) Tin Smith (103) Tin Smith (Selection Grade; Grade II; and III; Class II) (104) Tinker (105) Tailers (106) Turner (107) Upholsterer (108) Upholsterer (Grade II and III) (109) Painter Spray Class II (110) Wood Cutter (111) Wood Cutter Selection Grade (112) Wood Cutter Class II (113) Work Sircar (114) Welder (115) Welder Gas (116) Welder (Class II; Bridge work) (117) Well Sinker (118) White Washer (119) White Washer (Selection Grade; (Class II) (120) Wireman (121) Wireman (Grade II & III; Class I; Mechanic; Electrical) (122) White Washing & Colour Washing Man (123) Operator Phemuatic Tools (124) Operator (Fitter) (125) Boreman (126) Borer (127) Chipper (128) Chipper-cum-Grinder (129) Cook (Head); (130) Driller; (Well-Boring) (131) Driver (Loco/truck) (132) Electrician (Asstt.) (133) Mechanic (Tube-well) (134) Mistry (Steel; Tube-Well; Telephone) (135) Meter Reader (136) Meteorological Observer (137) Navghani (138) Operator (Batching Plant) Cinema Project; Clamp Shell; Compressor, Crane; Dorrick; Diesel Engine; Doser; Dragline; Drill; Dumper; Excavator; Fork Lift; Generator; Grader; Hack-Hammer & Pavement Breaker; Loader; Pump; Pile Driving; Scrapper; Screening Plant; Shoval; Tractor; Vibrator; Weight Batcher) (139) Railway Guards (140) Repairer (Battery) (141) Sharper Slotter (142) Sprayer (Asphalt) (143) Station Master (144) Surveyor (Silt)					

(1)	(2)				
(145) Trades-man (146) Train Examiner (147) Turner/Miller (148) Tyre Valcanisor (149) Work (Asstt.) (150) Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature	10.40	9.52	8.64	7.84	7.12
HIGHLY SKILLED :					
(1) Armature Winder Grade I (2) Blacksmith Grade I and Class I (3) Boilerman Grade I (4) Boilerman Foreman Grade I (5) Brick Layer Class I (6) Cable Joiner Grade I and (7) Carpenter Grade I and Class I (8) Celotex Cutter and Decorator (9) Chargeman Class I (10) Checker (Senior) (11) Driver Lorry Grade I; Motor Lorry Grade I; Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I; Road Roller Grade I; Pump Grade I; Pump Class I(12) Electrician Grade I and Class I (13) Fitter (Grade I; Class I; Pipe Class I; Head) (14) (Foreman (Asstt.) (15) Line Man Grade I (16) Mason (Skilled Grade I; Class I) (17) Mast Rigger Mechanic Class I and Class II (18) Mechanic (Head) or Electrician (19) Mechanic (Diesel Grade I; Road Roller Grade I; Air-conditioning Grade I; Class I; Air Conditioning (20) Mistry Grade I (21) Mistry (Airconditioning Grade I (22) Overseer (23) Overseer (Senior & Junior) (24) Painter (Grade I; Class I; Spray) (25) Plasterer (Mason) Class I) (26) Plumber (Head); Class I; Mistry Grade I) (27) Polisher (with spray) Grade I (28) Road Inspector Grade I (29) Sawyer Class I (30) Stone Cutter Class I (31) Stone Cutter Gr. I (32) Stone Chilsler Class I (33) Stone Mason Class I (34) Sub-Overseer (Qualified) (36) Tiler Class I (36) Tinsmith Grade I and Class I (37) Upholsterer Grade I (38) Varnisher Class I (39) Welder-cum-Fitter and Air-Conditioning Mechanic (40) Welder (Gas) Class I (41) White Washer Class I (42) Wireman Grade I; Class I (43) Wood Cutter Class I (44) Grinder (Tool) Grade I (45) Operator (Batching Plant Grade I; Clamp Shell Grade I; Compressor Gr. I; Crane Gr. I Diesel Engine Gr. I; Drill Gr. I Dumper Gr. I; Excavator Gr. I; Fork lift Gr. I; Generator Gr. I; Grader Gr. I; Leader Gr. I; Pile Driving Gr. I; Pump Gr. I; Scrapper Gr. I; Screening Plant Gr. I; Shovel Gr. I; Shovel & Dragline; Tractor Gr. I; Vibrator Gr. I; Rigger Gr. I; Rigger Gr. II (46) Sharper/Sletter Gr. I (47) Tradesman Class I (48) Turner/Miller Gr. I (49) Tyre Valcaniser Gr. I (50) Work (Asstt.) Gr. I (51) Any other categories by whatever name called which are of a highly skilled nature	13.00	11.90	10.80	9.80	8.90
CLERICAL :					
(1) M.C. Clerk (2) Munshi (Matriculate; Non-Matriculate) (3) Store Clerks (Matriculate; Non-Matriculate) (4) Store Issuer (5) Store Keeper (6) Store Keeper (Gr. I; II; Matriculate II; Non-Matriculate) (7) Tally Clerk (8) Time Keeper (9) Time-Keeper (Matriculate; NonMatriculate) (10) Tool Keeper (11) Work Munshi (12) Work Munshi (Subordinate) (13) Accounts Clerk (14) Clerks (15) Computor (16) Telephone Operator (17) Typists (18) Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature . .	10.40	9.52	8.64	7.84	7.12

Explanation :—For the purpose of this notification,—

(1) Area A, B-1, B-2 and C shall comprise all places as specified in the Annexure I to this notification including all places within a distance of eight kilometres from the periphery of the Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board Notified Area Committee of particular place; and Area 'D' shall comprise all the places not including in Areas A, B-1, B-2 and C.

(2) and the workmen, employed in scheduled employments in 'D' Class areas, where the Minimum Wages have been fixed on area wise basis and where the Central Government has sanctioned payment of Winter/Hill and other special allowance, may be paid 10 per cent extra of th minimum wages fixed or revised under the Act in addition to the minimum wages payable.

(3) Where in any area the wages fixed under this notification are lower than the wages fixed by the State Government for the corresponding scheduled employment for which it is the appropriate Government, the higher rates would be payable as minimum rates of wages under this notification.

(4)(a) "UNSKILLED" work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "SEMI-SKILLED" work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) "SKILLED" work is one which involves skill or comptence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(d) "HIGHHLY SKILLED" work is one which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks, acquired through intensive technical or professional training, or practical work-experience for long years and also requires of a work to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

(5) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

(6) The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates, and include also the wages for weekly day of rest.

(7) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 70% of the rates payable to adult workers of the appropriate catcogry.

ANNEXURE—I

Name of the State/ Union Territory	Class of Cities/Towns			
	A	B-1	B-2	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Andhra Pradesh	Hyderabad	—	—	Adoni, Anakapalle, Anantapur, Bandar (Masulipatam), Bheemavaram, Chirala, Chittor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakal, Guntur, Kakinada, Khammam, Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal, Nallore, Nizamabad, Ongole, Proddatur, Rajahmundry, Tenali, Tirupati, Vijepuri Vijayawada (Bezwada), Visakhapatnam (Vizagapatam), Vizianagaram, Warangal.
Bihar	—	—	Patna Dhanbad, Jamshedpur	Arrah, Bettia, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi., Bihar Sharif.
Chandigarh	—	—	—	Chandigarh.
Delhi	Delhi	—	—	—
Gujarat	—	Ahmedabad	Surat, Vadodara (Baroda)	Anand, Bhavnagar, Bhuj, Broach, Cambey, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mehsana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Rajkot, Surendranagar, Veraval.
Haryana	—	—	—	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Panipat, Rohtak, Sonepat, Yamunanagar.
Karnatak	Bangalore	—	—	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Davangere, Gadag-Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Hubli-Dharwar, Kochlar Gold Fields, Mandya, Mangalore, Mysore, Raichur, Shimoga, Tumkur.
Kerala	—	—	Cochin, Trivandrum	Alleppey, Badagara, Calicut (Kozhikode), Cannanore, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon.
Madhya Pradesh	—	—	Indore, Jabalpur Gwalior	Bhilainagar Industrial Township, Bhopal, Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg (Laskar), Khandwa, Mandsaur, Mhow (Cantt.), Murwara, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona	Sholapur	Achalpur town group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Bhulia, Dombivli, Godia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptec, Khamgaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Pimpri-Chinchwad, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.
Orissa	—	—	—	Berhampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Rourkela, Sambalpur.
Pondicherry	—	—	—	Pondicherry.
Punjab	—	—	Amritsar Ludhiana	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	—	—	Jaipur	Ajmer, Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.
Tamil Nadu	Madras	—	Coimbatore, Madurai, Salem, Tiruchirapalli (Trichinopoly).	Ambur, Aruppukkottai, Bodinayakanur, Cuddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadayanallur, Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Mayuram, Nagapattinam, Nagercoil, Palayamkottai, Pollachi, Pudukkottai, Rajapalayam, Srirangam, Srivilliputtur, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tirunelveli, Tiruppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambadi, Vellore, Villupuram, Virudhunagar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Uttar Pradesh	—	Kanpur Lucknow	Agra, Allahabad Varanasi (Banaras)	Aligarh (Koil Aligarh), Amroha, Bahraich, Banda, Barili, Badaun, Bulandshahar, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-cum Ayodhya, Farrukhabad-cum-Fathegarh, Fatehpur, Ferozabad, Gaziabad, Gonda, Gorakhpur Haldwani-cum-Kathgodam, Hapur, Hardwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Mathura, Maunath-Bhanjan, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Sharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	—	—	Asansol, Baidyabati, Bally, Bangaon, Bankura, Bansbaria, Barrackpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara, Budge Budge, Burdwan, Khampadni, Chandernagore, Cooch Behar, Durgapur, English-Bazar, Halishahar, Hooghly-chinsura, Jalpaiguri Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Krishnagar, Midnapur, Nabadwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Rishra, Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh, Ittarpara-Kotrung.

[S-32019(18)/75-WC(MW)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Sec.

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1976

का० आ० 1148.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की वेस्ट मुडिडिह कोलियरी, डाकघर सिजुआ, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 3 धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० की वेष्ट मुडिडिह कोलियरी, डाकघर सिजुआ, जिला धनबाद की, श्री रामेश्वर राम, मुन्शी को 11 फरवरी, 1975 से सेवा से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या एल-20012/182/75-डी० 3ए]

ORDER

New Delhi, the 6th March, 1976

S.O. 1148.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of West Mudidih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 3 Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of West Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Sijua Distt. Dhanbad is dismissing the services of Shri Rameshwar Ram, Munshi with effect from the 11th February, 1975 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

[No. L-20012/182/75-D. IIIA]

आदेश

का० आ० 1149.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की अकाशकीनारी कोलियरी, डाकघर कत्रासगढ़ (धनबाद) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की अकाशकीनारी कोलियरी, डाकघर कत्रासगढ़, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री सेवक राम, कार्यालय लिपिक को 25 अप्रैल, 1973 से काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या एल-20012/96/75 डी० III ए०]

ORDER

S.O. 1149.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Akashkinaree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Katrasgarh (Dhanbad) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 3 Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Akashkinaree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad is justified in stopping from work to Shri Sevak Ram, Office Clerk with effect from 25th April, 1973 ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

[No. L-20012/96/75 D-III-A]

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1976

का०आ० 1150.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कापासारा कोलियरी, कोल माईन्स अथारिटी लिमिटेड, क्षेत्र संख्या VI, डाकघर मुधमा (जिला धनबाद) (अब ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 3 धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी लि०, डाकघर मुधमा जिला धनबाद की कापासारा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की (1) श्री अनिल माहातो, खनिक को 17-11-74 और (2) श्री रामेश्वर ठाकुर, ट्रैमर को 7-11-74 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल०-20011/3/75-डी-III ए०]

ORDER

New Delhi, the 8th March, 1976

S.O. 1150.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kapasara Colliery Coal Mines Authority Ltd. Area No. VI, P.O. Mugma (Distt. Dhanbad) (now Eastern Coal fields Ltd.) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2 Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kapasara Colliery of M/s. Coal Mines Authority Ltd., P.O. Mugma (Distt. Dhanbad) in dismissing (1) Shri Anil Mahato, Miner with effect from 17-11-1974 and (2) Shri Rameshwar Thakur Trammer w.e.f. 7-11-1974 is justified if not, to what relief are the said workmen entitled ?"

[No. L-20011/3/75-D-III-A]

आदेश

का०आ० 1151.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की भुलनबरारेओ कोलियरी, डाकघर पथेरडिह (धनबाद) से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की भुलनबरारेओ कोलियरी, डाकघर पथेरडिह, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, सर्वश्री जी०पी० चौधरी, यू० एस० तिवारी और श्री जालिम राम, मुंशियों को 21-4-1975 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल० 20012/158/75-डी-3-ए]

ORDER

S.O. 1151.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bhulanbararco Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Patherdih (Dhanbad) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2 constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhulanbaraeo Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Patherdih, Distt. Dhanbad in dismissing S/Shri G. P. Choudhury, U. S. Tiwary and Sri Jalim Ram, all Munshies, with effect from 21-4-1975, is justified ? If not, to what relief are they entitled ?"

[No. L-20012/158/75-D III-A]

आदेश

का०आ० 1152.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

की खास जयरामपुर कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा (धनबाद) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं० 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की जयरामपपुर कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री भीम साव और शिवनाथ साव, ट्रक/ट्रैक्टर लोडरों को 1 जुलाई, 1975 से काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-20012/163/75-डी-IIIए]

ORDER

S.O. 1152.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khas Joyrampur Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Khas Jeenagora (Dhanbad) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 3 Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Khas Joyrampur Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Khas, Jeenagora, District Dhanbad is justified in stopping S/Shri Bhim Saw and Seonath Saw, Truck/Tractor Loader from work with effect from 1st July, 1975 ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?

[No. L-20012/163/75-D. IIIA]

आदेश

का०आ० 1153.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, की गनहूडिह कोलियरी, धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं० 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की गनहूडिह कोलियरी, डाकघर झरिया जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की 4 जुलाई, 1975 से श्री पी० डी० राय, मुन्शी की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-20012/178/75-डी-IIIए]
आर० पी० नरूला, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1153.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Ganhoodih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Scheduled hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 3 Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Ganhoodih Colliery of Messrs, Bharat Coking Coal Limited, Post Office, Jharia, District Dhanbad in dismissing the services of Shri P. D. Rai, Munshi with effect from 4th July, 1975 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?

[No. L-20012/178/75-D. IIIA]
R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1976

का०आ० 1154.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद को मुख्य खान निरीक्षक के मातहत खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[फाइल संख्या ए-12025/5/74-एम-1(ii)

New Delhi, the 9th March, 1976

S.O. 1154.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952, (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Krishna Murari Prasad as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[File No. A-12025/5/74MI (ii)]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1976

का०आ० 1155.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1681 तारीख 25 अप्रैल, 1969 को, जहां तक यह श्री बी० एस० रैंक से संबंधित है, विखंडित करती है।

[फाइल संख्या ए-39012/4/75-एम-1(ii)]

जे० सी० सक्सेना, अवर सचिव

New Delhi, the 8th March, 1976

S.O. 1155.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952, (35 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No. S.O. 1681 dated the 25th April, 1969, in so far as it relates to Shri B. S. Rank.

[File No. A. 39012/4/75-MI(ii)]

J. C. SAXENA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.